

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 1981

(प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 24 मार्च, 1981

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11)27
ध्यानाकर्षण सूचनाएं:-	
राज्य में कानून तथा व्यवस्था की विगड़ती हुई स्थिति तथा विशेषकर हिसार में जुर्मों के अधिक होने संबंधी	(11)29
नेमिंग आफ मैम्बर	(11)33
वाक आउट	(11)34
वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)35
नेम किये गये सदस्य को वापिस बुलाना	(11)40
वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)40

उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंग:-	
निगम/बोर्ड के सभापति या सरकार के अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पदनाम से लगाए गए आरोपों को कार्यवाही से निकालने संबंधी	(11)45
वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)45
नेमिंग आफ मैम्बर	(11)60
वाक आउट	(11)61
वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)62
बैठक का समय बढ़ाना	(11)75
वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)75
बैठक का समय बढ़ाना	(11)78
वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)78
वैयक्तिक स्पष्टीकरण:-	
चौधरी सतवीर सिंह मलिक द्वारा	(11)79

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 24 मार्च 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान अब सवाल होंगे।

Water Supply under the world Bank Scheme in Kathura Blcok of Tehsil Gohana

***2049. Sh. Bhale Ram:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state whether it is a fact that a scheme for the supply of water to certain villages in Kathura Block of Tehsil Gohana has recently been sanctioned under the world Bank Scheme; if so, the names of such villages together with the time by which the said scheme is likely to be implemented?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh): Yes, two schemes covering the under mentioned village have been sanctioned:-

Bhawar, Nazampur, Garahwala, Kohila, Gillaur Kalan and Gillaur Khurd.

The Schemes are likely to be implemented in 1982.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि जो स्कीमें सैंकान हुई हैं उनके लिए कितना फण्ड अलॉट हुआ है और इनके लिए जमीन कब ली गई थी ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, एक स्कीम के लिए 17.15 लाख रूपया दे दिया है और उसकी टोटल कास्ट 44.37 लाख रूपये है। दूसरी स्कीम पर 9.68 लाख रूपया खर्च आयेगा और उसके लिए चार लाख रूपया दे दिया गया है। ये स्कीमें 12/78 में सैंकान हुई थी। जमीन के बारे पहले झगड़ा पड़ गया था। यह वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत है। भायद मेरे लाया दोस्त को गलत फहमी हो गई है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की टोटल स्कीमें 52 थीं जिनमें 176 गांव इन्वाल्वड थे। उनमें से 89 गांवों में काम हो चुका है। वर्ल्ड बैंक से हमने कमिटमेन्ट की है कि अगस्त 1982 से पहले पहले तमाम स्कीमें चालू हो जाएंगी, कोई स्कीम पैडिंग नहीं रहेगी।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, वर्ल्ड बैंक की स्कीम जो कि 1978 में स्वीकृत की गयी थी, वह फ्लडिड एरियाज के लिए थी। इस स्कीम के तहत रोहतक और सोनीपत के जितने गांव हैं, वे कवर होते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता

हूँ कि 1978-79 में वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत जो गांव आए थे, उनमें कब तक यह स्कीम लागू कर दी जाएगी ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह जनरल टाइप का सवाल है। काफी गांव हैं, जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत आते हैं। आनरेबल मैम्बर अगर किसी स्पैसिफिक गांव का पूछें तो मैं बता देता हूँ। वैसे मैं उन्हें जिलावार ही सारी पोजीशन बता देता हूँ। अम्बाला के अन्दर 7 स्कीमों 23 गांवों के लिए थी। उनमें से 5 स्कीमों पूरी हो चुकी है और 2 पारिफाली कम्पलीट है। इसी तरह से गुड़गांव के अन्दर 31 गांवों के लिए 2 स्कीमों हैं। वहां पर बराबर काम चल रहा है। फरीदाबाद में एक स्कीम के तहत 8 गांव आते हैं जो कि लगभग पूरी हो चुकी है। हिसार में 19 स्कीमों हैं जोकि 59 गांवों को कवर करती हैं। उनमें से 5 पूरी हो चुकी हैं और एक पारिफाली कम्पलीट हुई है। जींद में 4 स्कीमों हैं जोकि 11 गांवों को कवर करती हैं और वहां पर अभी तक काम चालू है। सोनीपत के अन्दर 2 स्कीमों हैं जोकि 6 गांवों को कवर करती हैं। इसी तरह से सिरसा में 10 स्कीमों हैं जोकि 34 गांवों को कवर करती हैं जिनमें से 6 पूरी हो चुकी हैं और बाकी में काम चालू है। इस तरह से यह ब्रेक अप है जो मैंने अभी बताया है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, क्या जो स्कीमों पहले ही रूरल एरियाज में फंडेशन कर रही हैं और खास तौर पर वहां, जहां पर ओवर हैड टैन्क्स नहीं बने हैं उस गांव के एक कोने में तो पानी मिल जाता है और दूसरी कोने में प्रेशर न होने

की वजह से पानी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पर ओवर हैड टैन्क कब तक बना दिए जायेंगे ?

श्री लछमन सिंह: जब कोई वाटर सप्लाई स्कीम पूरी हो जाती है तो वहां ओवर हैड टैन्क्स बना दिया जाता है। वैसे ओवर हैड टैन्क्स जगह जगह बनये जा रहे हैं। कई बार लोहे और सीमेन्ट की कमी के कारण रूक जाता है और बाद में उसको रि-टैण्डर करना पड़ता है जिसकी वजह से काफी देरी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: क्या यह सरकार की पालिसी है कि जहां जहां वाटर सप्लाई स्कीम है वहां पर ओवर हैड टैन्क्स होने चाहिए ?

श्री लछमन सिंह: जी हां। जब हमारी स्कीम्ज पूरी हो जाती है तो नलके दे दिए जाते हैं और पानी चलता रहता है। जो स्कीम्ज पहले से चालू हैं, वहां ओवर हैड टैंक बनाने का प्रोवीजन है।

डा. बृजमोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने जिलावार स्कीम्ज का ब्यौरा दिया है। क्या कांस्टीच्यूएंसी वाइज इन स्कीम्ज के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इस समय कास्टीच्यूएंग्सी वाइज ब्यौरा मेरे पास नहीं हैं। आनरेबल मैम्बर इसके लिए अलग से नोटिस दें तो बता दिया जाएगा।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल कमेटीज की वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, क्या सरकार उनको टेक ओवर करने का विचार रखती हैं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल इससे सम्बन्धित सप्लीमैन्ट्री नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर को बता देना चाहता हूँ कि सरकार म्युनिसिपल कमेटीज को ऐसी स्कीम्ज के लिए कर्जा देती है और दूसरी हर तरह की मदद भी उन्हें देती है। क्योंकि उनके पास न कोई टैक्नोलोजी होती है और न ही कोई टैक्नीकल नो हाउ होती है। अगर म्युनिसिपल कमेटीज को फण्ड्ज की दिक्कत होती है, तो उनको हम कर्जा देते हैं। एल.आई.सी. और दूसरे सोर्सिज से भी हम उन्हें लोनज वगैरह दिलवाते हैं। सरकार की यह पालिसी है कि जहां जहां पर कमेटीज को कोई दिक्कत हो, उसको दूर किया जाए। हमने रोहतक के अन्दर भी इस काम के लिए पैसा दिया है। जहां तक टेक ओवर करने का सवाल है, इसमें हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। वैसे सभी म्युनिसिपल कमेटीज अपना काम आप ही चलाती हैं। अगर कोई म्युनिसिपल कमेटी यह लिखकर दे तो हम टेक ओवर कर सकते हैं हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं भी इस बात पर क्लयर नहीं हूँ कि जो वाटर सप्लाई स्कीम्ज म्युनिसिपल कमेटी की हैं, उनको पब्लिक हैल्थ विभाग रन करता है या म्युनिसिपल कमेटीज खुद रन करती है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब कई जगहों पर तो म्युनिसिपल कमेटीज खुद रन करती हैं और कई जगहों पर हमारा कंट्रोल है। जैसे कालका की जो म्युनिसिपल कमेटी है वह अपना काम खुद संभालती है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, सरकार ने पिछले सत्र में यह कहा था कि प्रदे 1 में म्युनिसिपल प्राजैक्ट्स के लिए अलग से वाटर एण्ड सैनीटरी बोर्ड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। उसके माध्यम से वर्ल्ड बैंक से थोड़े इंट्रैस्ट पर कर्जा लेकर म्युनिसिपल कमेटीज के वाटर सिस्टम को इम्पूव करने की योजना थी। क्या मंत्री महोदया बताएंगे कि वह योजना अब भी विचाराधीन है, अगर है तो उसे कब तक लागू कर देंगे ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर डाक्टर साहब इसके लिए अलग से नोटिस दें तो उन्हें डिटेल्ड रिप्लाय दे दिया जाएगा या फिर डाक्टर साहब थोड़ा सा टाइम निकालें ओर मेरे दफ्तर में आ जाएं तो बता दिया जाएगा। (ओर एवं व्यवधान)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन दल बदलुओं के दफ्तर में तो हम नहीं जा सकते। अगर बताना चाहें तो यहीं पर ही बता दें। (गोर)

Construction of Building of Civil Hospital at Bhiwani

***1949. Sh. Surinder Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the time by which the building of Civil Hospital, Bhiwani is likely to be completed according to its original plan; and

(b) whether it is a fact that some of the machinery being used in the Civil Hospital is being shifted from this Hospital to Rohtak?

Health and Tourism Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar):

(a) At present no time schedule is fixed for completion according to original plan of the building of General Hospital, Bhiwani.

(b) There is no such decision.

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि मूल योजना के अनुसार सिविल हस्पताल भिवानी का भवन पूर्ण किये जाने के लिए इस समय कोई अवधि नियत नहीं

है। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह काम कब तक पूरा किया जाएगा ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, 300 बिस्तर का हस्पताल पहले ही चालू हो चुका है। फण्ड्ज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इस काम को आगे टेक अप किया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह पता नहीं कि फण्ड्ज की सुविधा कब होगी और खास कर भिवानी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल के 'बी' के भाग में भिवानी के हस्पताल की मीनरी दूसरे हस्पतालों में ट्रािफ्ट करने के बारे में पूछा था। मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब दिया है कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। स्पीकर साहब, बगैर फैसले के वहां की मीनरी दूसरी जगहों पर भेज दी गई। कुछ सिरसा में भेज दी गई और कुछ रोहतक में भेज दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस मीनरी को वहां से वापिस मंगवाया जाएगा ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, ऐसा है कि जहां भी कोई मीनरी फालतू होती है, उसे दूसरी जगह, जहां जरूरत हो भेज दिया जाता है। वहां पर कुछ मीनरी फालतू थी और अगर वह वहां पड़ी रहती तो उसे जंग लग जाती। उसकी दूसरे हस्पताल में जरूरत थी, इसलिए वहां भेज दी गई।

डा. मंगल सैन: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ओरिजीनल प्लान के मुताबिक भिवानी का हस्पताल कितने बैड्ज का था ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: पहले यह 500 बैड्ज का हस्पताल मंजूर हुआ था लेकिन ज्यों ही 1977 में जनता सरकार आई जिसमें मैं भी मंत्री था और डा. मंगल सैन जी भी मंत्री थे, उस सरकार ने यह आदेश दिया कि इस हस्पताल को 500 बैड्ज की बजाए 300 बैड्ज का कर दिया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि भिवानी से कौन कौन सी मीनिरी उठाई गई और वह कहां कहां पर भेजी गई ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: सामान्य हस्पताल भिवानी में एक 200 एम.ए. की, एक 150 एम.ए. की, एक 500 एम.ए. की, दो 300-300 एम.ए. की तथा एक 30 एम.ए. की मीनिरी थीं
.... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: एम.ए. का मतलब क्या है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: यह एक्सरे मीनिरी होती है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: देखिये मैम्बर साहेबान आप मंत्री महोदय को पूरा जवाब देने के लिए समय नहीं देते और बीच में इन्ट्रूट कर रहे हैं। आप उनको सही जवाब देने के लिए समय दें।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह की वहां पर 6 एक्सरे मीन थीं। आज उनमें से वहां पर पांच मीन मौजूद हैं। क्योंकि वहां पर एक मीन फालतू रखी हुई थी और इस्तेमाल नहीं हो रही थी इसलिए वह वहां से उठा कर दूसरी जगह ले जाई गई। यह मीन रोहतक के हस्पताल में डिफ्ट की गई थी। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आपका मतलब है कि केवल एक मीन वहां से उठा कर डिफ्ट की गई ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जी हां।

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भिवानी में जो फालतू मीनरी पहुंची थी वह किस गलत फहमी में पहुंची थी ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब तो मंत्री महोदय दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले वह 500 बैडज का हस्पताल मंजूर हुआ था उसके बाद 300 बैडज का करने का फैसला हुआ। इसलिए जो सरप्लस मीनरी थी वह दूसरी जगह चली गई।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूँ कि वहाँ से सिर्फ एक ही एक्सरे मीन नहीं गई बल्कि और मीनें भी गई हैं। (गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को थोड़ा क्लीयर कर देता हूँ। भिवानी में 1975 में 500 बैड्ज का हस्पताल मंजूर हुआ था। बाद में जब कमला वर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर बनीं और डा. साहब नम्बर दो के मंत्री बने। (गोर) मेरे कहने का मतलब यह है कि डा. साहब का नम्बर चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरा ही था। (गोर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत बताने जा रहा था कि 1975 में वहाँ पर 500 बैड्ज का हस्पताल मंजूर हुआ था उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई और डा. कमला वर्मा जो उसमें हेल्थ मिनिस्टर थीं तो इन्होंने उसको काट कर 300 बैड्ज का कर दिया। (गोर)

श्रीमति डा. कमला वर्मा: उस टाइम मैं अकेली मंत्री नहीं थी, आप भी मंत्री थे।

चौधरी भजन लाल: उन दिनों में मैं नहीं था। (गोर) अध्यक्ष महोदय, वह ठीक बात थी और उसके बाद हम भी महसूस करते हैं कि भाहरों में अगर बहुत बड़ा हस्पताल बना दें और देहातों में न बनाएं तो यह देहातों के साथ बे-इंसाफी होगी। इसलिये हमने फैसला लिया कि भाहरों में जितने बड़े हस्पताल की जरूरत हो, उतना ही बनाना चाहिए और जरूरत से फालतू भाहरों

से काट कर देहातों में बनाना चाहिए ताकि देहात के आम गरीब आदमी को भी फ़ैसिलिटी मिल सके। इस बात को ध्यान में रख कर हमने देहातों में हस्पताल बनाने का फ़ैसला किया है, जो कि बनाने जा रहे हैं।

जहां तक मीनरी या सामान का ताल्लुक है, यदि किसी हस्पताल में सामान ज्यादा पड़ा हो और किसी दूसरे हस्पताल में सामान की जरूरत हो तो वह फालतू सामान हम कमी वाले हस्पताल में भेज देते हैं। अगर भिवानी में और सामान की जरूरत महसूस की गई तो हम दूसरे हस्पताल से वहां पर सामान भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक हस्पताल में तो फालतू सामान पड़ा खराब होता रहे और दूसरे में सामान की जरूरत हो तो उस हस्पताल में सामान न भेजना, अच्छी बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आज से 6 साल पहले एक मीन खरीदी गई थी जिसकी कीमत 2 लाख 52 हजार 276 रुपये थी। वह भिवानी के हस्पताल में रखी हुई थी। अभी हमने उस मीन को टैस्ट करवाया तो वह बिल्कुल नकारा पाई गई है। यदि हम इस तरह से मीनें रखेंगे तो मीनें नकारा हो जाएंगी। इसलिए हमने यह महसूस किया है कि यदि किसी हस्पताल में मीन फालतू पड़ी है और दूसरी हस्पताल में उसकी जरूरत हो तो उसे वहां भेज दिया जाए।

चौधरी हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1975 में 500 बैड्स का हस्पताल भिवानी में

मंजूर हुआ था। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि फण्ड्ज न होने की वजह से भिवानी में 500 बैड्ज का हस्पताल नहीं बना सकते और न ही हस्पताल को पूरा किए जाने के लिए इस समय कोई अवधि नियत की जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी की बात ठीक है या चीफ मिनिस्टर साहब की बात ठीक है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी यह फरमाया था कि जिस समय श्रीमति डा. कमला वर्मा हैल्थ मिनिस्टर थी, उस समय यह फैसला किया गया था कि भिवानी में 500 बैड्ज की बजाये 300 बैड्ज का हस्पताल बनाया जाएगा।

Mr. Speaker: Has a firm decision been taken that it will be 300 beds hospital instead of 500 beds?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जी हां, यह फर्म डिसिजन ही लिया गया है।

श्री अध्यक्ष: क्या 300 बैड्ज के हस्पताल का काम कम्पलीट हो चुका है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जी हां, कम्पलीट हो चुका है।

Land Irrigated in the State

***1962. Sh. Hiran Nand Arya:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total acreage of land being irrigated by the canal water together with the number of times for which the water is required for the crop of wheat in the State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): राज्य में वर्ष 1979-80 के दौरान नहरी पानी द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 4172317 एकड़ (1688452 हैक्टेयर) है। गेहूं की फसल के लिए 4 से 5 बार पानी की आवश्यकता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वर्ष 1977-78 और 1978-79 में कुल कितने रकबे को पानी मिला ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, वर्ष 1977-78 में रबी की फसल में 682782 हैक्टेयर जमीन को पानी मिला और खरीफ की फसल में 998838 हैक्टेयर जमीन को पानी मिला। वर्ष 1978-79 में रबी की फसल में 765957 हैक्टेयर और खरीफ की फसल में 922245 हैक्टेयर जमीन को पानी मिला। स्पीकर साहब, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक इरीगेशन में 27 परसेंट की वृद्धि हुई है और यह हर साल बढ़ती जा रही है।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि नहरी पानी द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 4172317 एकड़ है। तो क्या

मंत्री महोदय बताएंगे कि इस सिंचित क्षेत्र में से महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कितना रकबा है ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह सैपरेट क्वै चन है। माननीय सदस्य अलग से लिख कर के दें।

चौधरी अजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि गेहूं की फसल को 4 से 5 पानी की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो 4172317 सकड़ जमीन में पानी आया है वह एक बार ही आया है या 4-5 बार आया है ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, भायद माननीय सदस्य को यह पता नहीं कि इस दफा कई इलाकों में बारि । ज्यादा होने के कारण दो कारण दो दफा भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी उनमें एक पानी देने से ही फसल तैयार हो गई और और कई ऐसे इलाके थे जहां 6-6 दफा पानी देना पडत्रा।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि गेहूं की फसल को 4 से 5 पानी की आव यकता है। आम तौर पर देखने में आया है कि नहरी पानी की कमी की वजह से गेहूं की फसल को एक ही पानी मिलता है लेकिन किसानों को पूरा आबियाना ही देना पड़ता है। क्या मंत्री जी कोई ऐसा विचार करेंगे कि जिस फसल में एक ही पानी आया

है, जोकि न के बराबर है क्या उसका आबियाना उसके मुताबिक कम करेंगे।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, आज तक ऐसी कोई शिकायत किसी किसान ने नहीं की कि नहरी पानी की कमी की वजह से फसल को एक पानी मिला हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गेहूँ की फसल को 5-6 बारियां नहरी पानी की आती रही हैं।

श्रीमति डा. कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने दो बातें कही हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फसल को एक ही पानी देना पड़ा और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 5-6 पानी देने पड़े। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि जिन किसानों की फसल को एक पानी मिला है उनसे आबियाना एक पानी का ही लिया जाएगा या पूरा आबियाना लिया जाएगा ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मेरी बहिन डा. कमला वर्मा को एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं है। (गोर एवं विघ्न)

श्रीमति डा. कमला वर्मा: स्पीकर साहब, उत्तर पूरा नहीं दिया गया। खेती का ठेका अकेले इस भाई का नहीं है, मेरी खुद की जमीन है। मेरा रादौर क्षेत्र में गांव में घर है। मुझे एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पता है। मंत्री जी ने यह कैसे कह दिया कि एग्रीकल्चर के बारे में मुझे पता नहीं है। मंत्री जी को यह भाब्द वापिस लेने चाहिए। (गोर)

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, जिन खेतों में एक पानी दिया और बाद में बारि 1 होती रही उनमें दोबारा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर बहिन कमला वर्मा जी यह समझें कि जिस खेत को पानी की जरूरत नहीं है उसको पानी दिया जाए तो वह फसल ज्यादा पानी से खराब हो जाएगी। अगर एक खेत में एक पानी दे दिया और बाद में बारि 1 होती रही तो कोई जरूरी नहीं उसको दोबारा पानी दें। यह बात, मेरी बहिन कमला वर्मा की समझ में नहीं आ रही है। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा. कमला वर्मा जी का सवाल यह था कि अगर एक खेत में एक दफा पानी दिया जाता है तो उस किसान से एक पानी का आबियाना लिया जाएगा या पूरा आबियाना लिया जाएगा ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह तो एक्ट में है कि आबियाना पूरा लिया जाएगा। (गोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, वह रिकार्ड न किया जाए। (गोर)

10.00 बजे

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी हाउस को बताया कि नहरों से कहीं दो बार पानी दिया जाता है, कहीं तीन बार दिया जाता है और अगर कुदरत की तरफ से बारि ा हो गई हो तो एक आध बार पानी दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि बरसात की वजह से जहां एक आध पानी दिया जाता है वहां आबियाना वसूल किया जाए और अगर पूरा दिया जाये तो पूरा आबियाना वसूल किया जाए ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आबियाना पूरा किया जाएगा। (व्यवधान) यह चीज प्रैक्टिकेबल नहीं हैं क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो कम आबियाना लिया जाए। इस चीज को असैस करना बड़ा मु् कल हो जायेगा कि कितना पानी लगा है, इसलिए यह प्रैक्टिकेबल नहीं है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं यह बात साफ कर देता हूं कि जब किसान की फसल खराब हो जाये या जाल जाये तो फसल की गिरदावरी की जाती है और जितना खराबा होता है, उस लिहाज से आबियाने में छूट दी जाती है।

Production of Income certificate by Backward Classes persons

***2069. Sh. Jai Narain Verma:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether it is a fact that the income certificate is required to be given by the

unemployed persons belonging to the Backward Classes alongwith the certificate of Backward Classes to get their names registered with the Employment Exchanges?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
जी नहीं।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मेरे सप्लीमेंटरी के तीन प्वायंट्स हैं, अगर आप इजाजत दें तो सारे प्वायंट्स इकट्ठे ही कह दूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगर छोटे छोटे प्वायंट्स हैं तो एक बार ही कह दें और अगर लम्बे हैं तो अलग अलग कह लें। (व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में नाम दर्ज करवाने के लिए बैकवर्ड क्लास के सर्तिफिकेट के साथ ही साथ एक सर्तिफिकेट अपनी आमदनी का भी देना पड़ता है, इन्होंने जवाब दिया 'नहीं'। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब किसी ए, बी, सी को बैकवर्ड क्लास का सर्तिफिकेट देते हैं तो इतना ही लिखना काफी नहीं होगा कि वह व्यक्ति घोशित किये हुए पिछड़े इलाके से या बैकवर्ड क्लास से सम्बन्ध रखता है ? क्या यह सही है कि जब व्यक्ति सर्तिफिकेट लेने के लिए जाता है तो उसको लिखना पड़ता है कि उसकी आमदनी इतनी है, इससे अधिक नहीं है ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: आमदनी का सर्टिफिकेट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाने के लिए देना पड़ता, केवल यह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वह आदमी बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखता है या नहीं। इसमें आमदनी का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई भाक नहीं है लेकिन मैंने एक स्पैसिफिक क्वेरी पूछा था कि जो इलाके या जातियां हरियाणा सरकार ने पिछड़ी हुई घोशित की हैं, अगर वह व्यक्ति इनसे सम्बन्ध रखता है तो क्या इतना लिखना काफी नहीं होगा कि वह फलां जाति से सम्बन्ध रखता है ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: इतना ही काफी है। इतना लिखने के बाद एस.डी.एम. से तसदीक रवाना पड़ेगा और फिर वह व्यक्ति एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा सकता है। (व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, इसके इलावा यह भी लिखना पड़ता है कि उसकी आमदनी निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है और इस चीज को प्रमाणित करवाना पड़ता है, तभी नाम दर्ज हो सकता है। आप इस बात की इन्क्वायरी करवा लें, आमदनी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है।

चौधरी मेहर सिंह राठी: अगर ऐसा है तो मैं हिदायत जारी कर दूंगा। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाने से पहले उसको यह प्रमाण देना पड़ता है कि वह बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखता है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार, एस.डी.ओ. (सिविल) बी.डी. एंड पी.ओ. या जी.ए.टू. डी.सी. से तसदीक करवाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या परफौर्मा में आमदनी का कोई जिक्र है ?

चौधरी भजन लाल: परफौर्मा में कोई जिक्र नहीं है। (व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: जो कुछ परफौर्मा में लिखा है, वह मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है:—

“On the basis of evidence adduced before me, I am satisfied that Sh..... S/o Sh. resident of (place) Tehsil District belongs to the caste which has been declared as Backward Class in Haryana.”

इस परफौर्मा में आमदनी के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, एस.डी.एम. या तहसीलदार के सामने जब बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसको एप्लाई करना पड़ता है। उससे बाकायदा लिखवाया जाता है कि आमदनी का सर्टिफिकेट पे 1 करें, इसके बिना सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): अगर कोई स्पैसिफिक एग्जैम्पल आपके पास हो तो वह बतायें। (व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, अगर कोई इकोनौमीकली बैकवर्ड है तो वह अपनी आमदनी का सर्टिफिकेट देगा। लेकिन जो व्यक्ति बैकवर्ड क्लास के नाम से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवाना चाहता है, उसके लिए इस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।

श्रम उप-मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: क्वै चन आवर में कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

चौधरी लाल सिंह: मैं आपकी इजाजत से इस सवाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बोल लीजिए। (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूँ कि बैकवर्ड जातियां भारत सरकार की तरफ से घोषित की हुई हैं और इनका नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से ही हुआ है। बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाकायदा फार्म बने हुए हैं और उसमें यह बताना पड़ता है कि वह बैकवर्ड क्लास की कौन सी जाति से ताल्लुक रखता है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह महकमा चौधरी लाल सिंह को दे दिया जाए, ये जवाब अच्छा देते हैं।

Mr. Speaker: The Hon. Minister has given a very clear out reply. इसके बावजूद भी अगर कोई आफिसर किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के एप्लीकेंट से, उसकी फाइनेंशियल बैकवर्डनेस का सर्टिफिकेट मांगता है तो ऐसी एग्जैम्पल मंत्री महोदय के नोटिस में लानी चाहिए।

श्री जय नारायण वर्मा: क्या मंत्री महोदय हाउस में अ योर करेंगे कि दोबारा किसी से इस किस्म का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: हम इसके बारे में दोबारा सर्कुलर जारी कर देंगे ताकि कोई आफिसर फाइनेंशियल बैकवर्डनेस का सर्टिफिकेट न मांगे।

Water supply group schemes of Tehsil Panipat.

***2065. Ch. Satvir Singh Malik:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the date on which the group schemes of water supply to viillages Kalkha and Alupur of Tehsil Panipat were sanctioned together with the time by which work thereon is likely to be started?

श्रम उप-मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्कीमों का 25.6.79 को प्र शासकीय अनुमोदन दिया गया लेकिन कोई धनराशि उपलब्ध नहीं की गई।

कोई भी निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह सैनिटरी बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध करने पर निर्भर करता है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदन ने कहा है .

.....

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने बहुत क्लीयर कट जवाब दिया है और मैं समझता हूँ कि इस पर सप्लीमेंटरी क्वैश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। नैक्स्ट क्वैश्चन प्लीज।

Recruitment of Constables in the Police Department

***2091. Ch. Ishwar Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) the district-wise number of Constables recruited during the last year together with the number of Harijans amongst them; and

(b) the district wise number of robberies and dacoitites committed in the State during the period as referred to in part (a) above together with the number of cases which are yet to be traced out?

Home Minister (Sh. Kanahiya Lal Poswal):

(a) and (b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) the district wise number of Constables during the last year together with the number of Harijans amongst them is as under:-

Name of District	Number of Constables recruited last year (1980)	Number of Harijan Constables amongst them
1	2	3
Ambala	54	11
Karnal	40	5
Kurukshetra	44	9
Jind	38	7

Hissar	13	5
Narnaul	12	5
Bhiwani	21	6
Sirsa	25	3
Gurgaon	24	5
Faridabad	84	10
Sonepat	44	2
Rohtak	46	11
Total	445	79

(b) In all 19 cases of dacoities and 63 cases of robberies were registered during the calender year, 1980. Out of these cases only 9 cases of dacoity and 6 cases of robbery are yet to be traced out. Efforts are afoot to trace out these cases. The district-wise break up of dacoity/robbery cases is given below:-

District	Cases Registered		Cases yet to be traced out	
	Dacoity	Robbery	Dacoity	Robbery
Ambala		5		
Kurukshetra	1	9	1	

Karnal	6	8	3	
Sonepat	2	2	1	1
Gurgaon	1	8	1	2
Faridabad	3	5	1	
Rohtak	1	7		1
Hissar	1	6		
Narnaul	2	3	1	
Bhiwani	1	5		
Sirsa				
Jind	1	5	1	2
Total	19	63	9	6

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, पुलिस में जिलावार जो कांस्टेबलज भर्ती किए गए उनमें हरिजनों की संख्या मैंने पूछी थी। करनाल जिला में 40 में से 5 सिपाही हरिजन भर्ती किए गए जबकि 8 होने चाहिए थे। तीन सीटें अभी खाली हैं। सिरसा में 25 में से 3 लिए गए जबकि 5 भर्ती किए जाने चाहिए थे। 2 जगहें यहां खाली हैं। फरीदाबाद में 84 में से 10 लिए गए जबकि 16 लिये जाने चाहिए थे। 6 जगहें वहां खाली हैं। इसी तरह से सोनीपत में 44 में से 9 सीटें हरिजनों की बनती थी लेकिन केवल

2 लिए गए। 7 जगहें यहां खाली है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरिजनों की पूरी भर्ती न करने का क्या कारण था और क्या इस कमी को अब पूरा किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: ओवरआल टोटल में इनकी सीट पूरी हैं या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: पूरी नहीं हैं।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट-वाइज टोटल पूरा होना चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नहीं। वैसे ओवरआल टोटल भी पूरा नहीं है। 18 जगहों की कमी है।

श्री अध्यक्ष: कुल 445 कांस्टेबल भर्ती किए गए और 445 का 20 परसेंट 89 यबनता है जबकि भर्ती 79 हुए हैं। There is a Short fall of 10.

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में परसेंटेज काफी कम रही है लेकिन कुछ में ठीक है। ओवरआल 10 की कमी रही है। हम इसको पूरा करेंगे। हम कोि । । करेंगे कि अगली भर्ती में इसको पूरा कर दिया जाए। रिक्रूटमेंट पूरी न होने की यह वजह थी कि पूरी मैयरमेंट और मैडिकली फिट आदमी अवेलेबल नहीं थे।

Mr. Speaker: I would also like to know whether there is any difference in the physical standard laid down for the general category and the Scheduled Castes?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: इसके बारे में स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि हरिजनों के लिए पांच साल एज में एक इंच हाईट में और एक इंच चैस्ट में रिलैक्सेशन है। ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन है। दूसरी जातियों के मैट्रिक लड़कों को भर्ती किया जाता है जबकि हरिजन नॉन-मैट्रिक भी लिए जा सकते हैं।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि हरिजनों की भर्ती पूरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि फिजिकली फिट लोग इनको नहीं मिले जबकि फैक्ट यह है कि बहुत से मैट्रिक पास हरिजन भी अवेलेबल थे। क्या मंत्री जी बातयें कि बेटिंग लिस्ट में भी कुछ लड़के रखे हैं या नई भर्ती की जाएगी ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, मैं हाउस को अ योरेंस दे चुका हूँ कि अगली भर्ती में हम इस परसेंटेज को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हुई है, इसे कब तक पूरा किया जाएगा और पिछली जो कमी रह गई हसे भी पूरा किया जाएगा या नहीं ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, पहले की कोई ज्यादा कमी नहीं थी। उसको हमने इम्पूव किया है।

कांस्टेबलज की हमारी जो टोटल स्ट्रैन्थ है उसके 18 परसेंट तक इनकी रिक्रूटमेंट को हम ले आए हैं।

चौधरी गया लाल: स्पीकर साहब, पुलिस में हरिजनों की संख्या पहले ही बहुत कम है। इस भाँटफाल को पूरा करने के लिए ज्यादा हरिजन लिए जाने चाहिए थे।

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ने बताया है कि केवल दो परसेंट की कमी है।

चौधरी गया लाल: स्पीकर साहब, जिला फरीदाबाद में 84 में से केवल 10 हरिजन भर्ती किए गए हैं जबकि 17 किए जाने चाहिए थे। सोनीपत जिले में 44 सीटों के अगेन्सट केवल 2 हरिजन लिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि ओवरआल टोटल में केवल 10 की कमी है।

चौधरी गया लाल: क्या यह कमी वेटिंग लिस्ट से पूरी की जाएगी या नई भर्ती द्वारा पूरी की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब पहले आ चुका है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, कांस्टेबलज में इस समय हमारी रिजर्वे 11 आफ पोस्टस 12 परसेंट है जबकि 20 परसेंट होनी चाहिए थी। इसलिए इसमें 8 परसेंट का गैप है दो परसेंट का नहीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने जब कहा है कि 2 परसेंट की कमी है, उसे डाउट करने की कोई गुंजाइ 1 नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: पीछे जो फिगरज मांगी गई थी उनके मुताबिक 8 परसेंट की कमी थी। सारे हरियाणा में केवल एक हरिजन डी.एस.पी. है। इंस्पैक्टर्ज और सब-इंस्पैक्टर्ज की परसेंटेज 3-4 से ज्यादा नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस भाौर्टफाल को पूरा करने की अ योरेंस हाउस को देंगे ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को और क्लीयर कर देता हूं। हमारे कुल कांस्टेबलज 12273 है। इनमें से रिजर्वेड कास्ट्स 2175 हैं। इस तरह से इसमें रिजर्वेड 18 परसेंट हो गई। लेकिन चूंकि पहले रिजर्वेड कास्ट्स कांस्टेबलज कम थे इसलिए हैड कांस्टेबलज, सब-इंस्पैक्टर्ज और इंस्पैक्टर्ज आदि कम बने। अब जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसमें 20 परसेंट रिक्रूटमेंट हर जगह हो रही है।

कैप्टन मांगे राम: क्या मंत्री जी बताएंगे कि भर्ती में जो हरिजनों की कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए कोई स्पैशल रिक्रूटमेंट करेंगे ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: सर, पुलिस की भर्ती हर तीसरे चौथे महीने होती रहती है। मैंने हाउस को अ योरेंस दी है कि उसमें इस कमी को पूरा कर देंगे।

चौधरी भागमल: स्पीकर साहब, जिन जिलों में कम रिक्रूटमेंट हुई है, वहां कोई वेटिंग लिस्ट तो रखी होगी। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमी को उस वेटिंग लिस्ट से पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब ने अ योरेंस दे दी है कि अब जब भी जगह खाली होगी तो डिप्लोम कास्टस का कोटा पूरा कर दिया जाएगा। इस पर मैं समझता हूं कि अब कोई फरदर डिस्कान की गुंजाई नहीं है।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, हरिजनों में कई क्लासिज हैं जैसे धानक, भंगी, चमार आदि। क्या मंत्री जी बताएंगे कि हरिजनों का क्लासिवाइज कोटा रिजर्व है, या सबके लिए इकट्ठी रिजर्व है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, जो भी हरिजन अवेलेबल होता है, उसे ले लेते हैं।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि सन् 1980 में 19 केस डकैती के दर्ज हुए हैं और 63 केस रौबरी के दर्ज हुए हैं। इनमें से 9 केस डकैती तथा 6 केस लूट के अनट्रेस्ड हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि आया ये मुलाजिम पकड़े ही नहीं गये या रौबरी का माल बरामद नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष: अगर हरेक केस की वजुहात में जाये तो बड़ा मुक्ति कल होगा।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, मैं कलीयरी कर देता हूँ। 19 केस डकैती के रजिस्टर्ड हुए जिनमें से 10 केस ट्रेस आउट हो गये। एक केस में कनविकान हुई, दो केसिज में इकविट हुए सात केसजि कोर्ट में पेंडिंग हैं और नो केसिज अन्डर इनवैस्टीगेशन हैं।

श्री अध्यक्ष: वे यह पूछना चाहते हैं कि जो नो केसिज अनट्रेसड हैं, वे किस वजह से हैं ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, ये अन-ट्रेसड नहीं हैं बल्कि अन्डर इनवैस्टीगेशन हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह औजला: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने जवाब में कहा है कि 63 केसजि रौबरी के हैं जिनमें 6 केसिज में अभी तफती पूर्य करने बाकी है। इसी प्रकार से 19 केसिज डकैती के हैं उनमें से 9 केसिज में इन्वैस्टीगेशन पूर्य करनी बाकी है। इन अन-ट्रेसड केसिज की परसैन्टेज 47 के करीब बैठती है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट इससे सैटिसफाइड है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: हम तो कोशिश करते हैं कि सौ परसैन्ट रिकवरी हो। सरकार कोशिश कर रही है कि ये केसिज ट्रेस आउट हों।

Surplus Land in Jhajjar Constituency

***2125. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Revenur be pleased to state:-

(a) the total area of land declared surplus in Jhajjar Constituency of Rohtak District since 1-1-1977 up-to-date;

(b) whether nay ara of land referred to abve has ben allotted to the Ex-servicemen, landless persons belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes; if so, the details thereof indicating the names of teh persons village-wise; and

(c) whether the possession of land so allotted has also been delivered to the persons referred to abve; if not, the reasons therefor?

Revenue Minister (Ch. Sher Singh):

(a) 195 Kanals 5 Marlas.

(b) Yes. A statement is laid on the Table of the House.

(c) Yes.

STATEMENT

The details of the area allotted to the Ex-servicemen, landless persons belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes are as under:-

1. Ex-Servicement Nil

2. (a) Landless persons belonging to the Scheduled Castes:

Sr.	Name of Allottee	Name of Village	Area Allotted	
			Kanals	Marlas
1	Sh. Bani Singh S/o Sh. Ram Jiwan	Mundhera	25	7
2	Sh. Itbari S/o Sh. Chand	Kheri-Taluka - Patoda	8	0
3	Sh. Khaki S/o Sh. Phusan	Kheri-Taluka - Patoda	8	0
4	Sh. Gini S/o Sh. Hansu	Kheri-Taluka - Patoda	8	0
5	Sh. Kashmiri Lal S/o Sh. Phusan	Kheri-Taluka - Patoda	8	0

(b) Landless persons belonging to Backward Classes:

Sr.	Name of Allottee	Name of Village	Area Allotted	
			Kanals	Marlas
1	Sh. Kishan Chand S/o Sh. Lok Ram	Kheri-Taluka - Patoda	8	0
2	Sh. Devender S/o Sh. Jangli Ram	Kheri-Taluka - Patoda	8	0

कैप्टन मांगे राम: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्यूएंसी झज्जर में 195 कनाल पांच मरले जमीन अलाट की गई है। उसमें एक्स सर्विसमें, बैकवर्ड और रिटायर्ड कास्ट्स कितने हैं, उसका भी जवाब मिनिस्टर महोदय ने दे दिया। मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि पूरी स्टेट के अन्दर कितनी जमीन बाकी है जो अभी लोगों को देनी है।

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने खासतौर पर झज्जर कांस्टीच्यूएंसी के बारे में पूछा था कि 1-1-1977 से आज तक किन-किन लोगों को जमीन अलाट की है, उसका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, सरकार ने जो जमीन लोगों को अलाट की है। उसमें एक आदमी को छोड़कर बाकियों को आठ-आठ कनाल और कुछ मरले अलाट की है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या आठ कनाल जमीन देने से उनका गुजारा हो सकता है ? कम से कम उनको पांच एकड़ तो जमीन दें ताकि उनका गुजारा हो सके। क्या एक एकड़ जमीन से उनकी फैमिली का गुजारा हो सकता है ?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, इसमें एस.डी.ओ. (सिविल) अलाटमेंट अथोरिटी है, वह इसका फैसला करती हैं और सी क्लास कैटगरी की जमीन दो हैक्टेयर तक दी जा सकती है।

कोई ए क्लास जमीन होती है, कोई बी क्लास जमीन होती है और कोई सी क्लास जमीन होती है, इसलिए depending upon the class and value of land, कई जगह एक एक एकड़ दी जाती है, कई जगह तीन एकड़ भी दी जाती है और कई जगह 5 एकड़ भी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: बाबू मूल चन्द जैन जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। फ़ैगमेन्टे इन आफ लैन्ड होल्डिंग्स को एवायड करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी साइड पर आप एक एक एकड़ जमीन अलाट कर रहे हैं। इस तरह से उनका गुजारा कैसे होगा ? यह ठीक बात है कि वह जमीन एक लाख की है या डेढ़ लाख की है अगर बेचने के लिए देनी है तो दूसरी बात है लेकिन अगर कायदा करने के लिए देनी है तो एक एकड़ जमीन देने का कोई फायदा नहीं है। (विधन) I think the Government should examine this question.

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के तहत एक स्कीम 1976 में बनी थी उस स्कीम के तहत जमीन को डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। उसमें सात-आठ कैटेगरीज दी गई हैं। जिनको जमीन अलाट की जाती है सी क्लास कैटेगरी की जमीन दो हैक्टेयर देते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि इससे गुजारा नहीं हो सकता तो इसके बारे में भी देख लेंगे कि और क्या रियायत हो सकती है।

श्री भागी राम: मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 195 कलान पांच मरले जमीन अलाट की गई है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि झज्जर कांस्टीच्यूएंसी में इतनी ही जमीन सरप्लस है या और भी है ? बिना जमीन वाले जो रह गये उनके लिए सरकार क्या कर रही है ?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, इस सवाल में पूछा गया था कि रोहतक जिले की झज्जर कांस्टीच्यूएंसी में 1-1-1977 से अब तक कितना रकबा सरप्लस घोशित किया है। उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, जिन लोगों को सरप्लस लैन्ड अलाट की जाती है उनके लिए रास्ते का कोई प्रावधान नहीं होता है। इस प्रकार के बहुत से केसिज है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या उनको आने जाने के लिए रास्ता दिलाने के विषय में सरकार गौर करेगी ?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में कई बार विचार किया गया और कैबेनिअ में भी कई बार गौर हुआ। इसमें फाईनैस डिपार्टमेंट वाले पूछते हैं कि रास्ते के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए कितना पैसा चाहिए। दूसरे जब कन्सोलीडे ान होती है तो उस वक्त भी हर किल्ले या हर जमीन को रास्ता नहीं दिया जाता (गोर) अब हमने फ़ैसला किया है कि अगर कहीं ऐसी दिक्कत आयेगी तो एस.डी.ओ. (सिविल) डी.सी.

की माफ़त गवर्नमेंट को लिखें कि इसको रास्ते के लिए दिक्कत आ रही है। इस बारे में जरूर गौर करेंगे और जहां पर रास्ते की जरूरत होगी वहां जरूर रास्ते दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Block Development and Panchayat Officers in the State.

***2186. Ch. Zile Singh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state:-

(a) the total number of Block Development and Panchayat Officers and Social Education and Panchayat Officers in the State;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the pay scale of the Social Education and Panchayat Officers referred to in part(a) above; and

(c) whether there is also any proposal under consideration of the Government to open new Block Headquarters in the State; if so, the time by which these are likely to be opened?

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह):

(क) राज्य में खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों की संख्या : 107

राज्य में समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारियों की संख्या : 92

(ख) हां।

(ग) (1) हां।

(2) तकरीबन दो महीने।

Cases of Murders in the State

***2213. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Home be pleased to state the district-wise total number of cases of murder registered in the State during the period from 1-1-80 to 1-1-81 ?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): हरियाणा राज्य में कत्ल के मुकदमों की संख्या 364 हैं, जिनका जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	जिला	कत्ल के मुकदमों की संख्या
-------------	------	---------------------------

1	अम्बाला	30
2	कुरुक्षेत्र	36
3	करनाल	41
4	जीन्द	28
5	हिसार	52
6	भिवानी	23
7	सिरसा	24
8	गुड़गांव	24
9	फरीदाबाद	24
10	रोहतक	28
11	सोनीपत	28
12	नारनौल	26
जोड़		364

Energisation of Tubewells in the State

***2165. Ch. Rizaq Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the division-wise and month-wise number of Tubewells energised in the State during the period from July, 1979 to-date; and

(b) the division-wise number of applications for Tubewell connections pending as on 31-1-1981.

(i) for a period of over three months; and

(ii) for a period of six months or above?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Division wise and Month wise number of tubewells energised in the State during the period from July, 1979 to January, 1981.

Sr	Name of Div.	7/79	8/79	9/79	10/79	11/79	12/79	1/80	2/80	3/80	4/80	5/80	6/80	7/80	8/80	9/80	10/80	11/80	12/80	1/81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Ambala	13	44	10	30	29	30	28	17	17	26	32	40	35	28	35	21	16	38	9
2	Shahbad	67	89	65	82	94	78	55	50	64	95	91	106	121	134	130	133	116	176	60
3	Jagadhri S/U	39	53	22	27	60	38	57	47	15	23	34	30	20	20	19	19	21	37	45
4	Kuruksheetra	190	168	43	47	90	101	74	28	73	48	31	84	126	104	138	39	85	81	21
5	Pinjore	16	30	20	16	42	24	12	24	17	6	20	26	26	17	32	27	53	31	23
6	Yamuna									34	19	61	67	94	60	58	19	28	53	21

	Nagar																			
7	Karnal City	61	48	19	30	60	69	50	40	27	15	27	59	58	57	57	28	25	39	21
8	Karnal S/U	13 8	13 4	66	18 5	20 0	26 8	22 9	10 5	11 2	10 4	11 8	15 0	19 2	24 4	23 7	85	14 9	16 2	104
9	Panipat City	34	38	30	64	10 1	91	60	96	76	75	51	68	85	85	61	62	62	50	60
10	Panipat S/U	17 8	16 3	13 6	20 8	19 5	24 5	25 0	26 0	23 5	17 8	14 7	15 6	14 8	16 7	14 7	12 4	11 9	17 3	131
11	Kaithal	16 1	14 6	76	19 9	23 0	13 4	14 5	16 9	14 4	16 6	16 7	12 3	15 3	19 5	14 2	15 6	10 6	95	53
12	Pehowa	25 7	16 8	10 3	16 6	18 6	18 8	12 7	94	12 1	88	14 8	95	27 1	10 9	89	79	75	64	20
13	Delhi	5	5	12	23	33	49	32	29	21	17	9	12	14	13	22	17	46	35	40
14	Gurgao n	7	38	40	13 5	13 4	17 2	91	74	52	37	16	6	7	27	16	85	15 7	17 3	73

15	Rewari	6	16		10 9	23 0	19 5	72	52	19	13	4	22	23	30	17	61	10 2	10 5	63
16	Sonepat	25	34	41	70	14 0	10 1	75	59	80	58	58	35	33	65	66	56	10 8	85	59
17	Dharuhera											6	5	16	6	41	66	13 4	13 0	76
18	Faridabad				3	1	1	1		1	2				1	1	1	5	11	2
19	Ballabgarh	15	23	36	15 1	28 9	19 7	12 2	12 9	68	46	59	63	85	28	54	11 5	17 2	16 3	150
20	Palwal	20	31	40	21 4	24 0	20 0	97	60	37	82	34	53	11	31	96	14 0	29 0	20 7	90
21	Hissar	2	5	11	13	10	6	7	56	15	17	17	10	13	9	7	12	17	14	16
22	Sirsa	74	70	45	21	64	45	39	47	56	85	70	30	63	83	76	11 3	69	49	68
23	Fatehabad	94	70	36	70	55	62	44	56	88	86	85	48	38	55	23	92	81	99	75

	ad																			
24	Bhiwani	1	8	15	45	71	36	28	29	16	17	11	23	12	16	28	49	39	63	36
25	Hansi	2	4	2	22	32	21	18	42	33	23	20	29	9	11	38	29	35	38	30
26	Rohtak City		3	3	16	16	9	10	5	2	5	5	4	3	4	2	6	10	12	9
27	Rohtak S/U	6	5	11	31	51	30	23	29	22	19	17	9	15	10	17	40	39	20	32
28	Jhjjar	12	30	37	15 2	24 8	12 2	72	43	21	21	27	16	2	2	69	59	21 3	19 2	78
29	Dadri	23	9	43	20 1	19 0	98	51	60	44	31	22	27	25	44	45	12 1	16 6	15 6	83
30	Jind	67	67	65	13 6	18 9	76	94	57	66	94	56	42	76	53	51	59	68	59	100
31	Narnaul	25	47	80	28 1	42 4	18 1	58	39	36	13	7			25	48	11 1	44 4	80	30

(b) Division wise number of applications for tubewells connections pending as on 31.1.1981

Sr.	Name of Div.	Number of applications pending for a period of over 3 months	Number of applications pending for a period of 6 months or above
1	Ambala	194	58
2	Shahbad	599	342
3	Yamuna Nagar	230	390
4	Jagadhri	257	111
5	Kurukshetra	396	863
6	Pinjore	219	70
7	Karnal City	109	716
8	Karnal S/U	464	1853
9	Panipat City	84	12
10	Panipat S/U	527	1289
11	Kaithal	371	2160
12	Pehowa	206	1335
13	Delhi	74	8
14	Gurgaon	112	42

15	Rewari	237	1205
16	Dharudhera	211	677
17	Sonepat	434	26
18	Faridabad		
19	Ballabgarh	37	
20	Palwal	157	36
21	Hissar	29	4
22	Sirsa	252	488
23	Fatehabad	193	931
24	Hansi	115	65
25	Bhiwani	77	78
26	Rohtak City	20	
27	Rohtak S/U	78	77
28	Jhajjar	257	19
29	Dadri	379	93
30	Jind	456	314
31	Narnaul	203	1002
	Total	6977	14264

Cost of Production of Paddy and Sugarcane

***2263. Swami Agnivesh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the per quintal cost of production of paddy and sugarcane together with the procurement price fixed for these crops during the year 1980-81 in the State?

Agriculture Minister (Sh. Shamsheer Singh): The cost of production of paddy per quintal inclusive of 15% charges towards risk and management for the year 1980-81 was Rs. 101/-. The Government of India fixed a procurement price of Rs. 105/- per quintal for common coarse varieties of I-R-8 and Jaya, and Rs. 109/- and Rs. 113/- per quintal for fine varieties like Begmi and HM-95 and super fine varieties like Palmal and PR-106 respectively for the year 1980-81.

The cost of production of sugarcane per quintal inclusive of risk and management charges for 1980-81 was Rs. 18.08. The Government of India fixed statutory price of Rs. 13/- per quintal for sugarcane for 1980-81 linked to a recovery of 8.5% with a premium of 15.2941 paise for every increase of 0.1% recovery. The State Government, however, fixed agreed price of Rs. 23/- per quintal from the date of start of crushing of sugarcane by Sugar Mills till 7th March, 1981 which has been increased to Rs. 26/- per quintal from 8th March, 1981.

Operation Division of Haryana Electricity Board at Tohana

***2243. Ch. Karam Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to create a full fledged Operation Division of Haryana State Electricity Board at Tohana; and

(b) if so, the time by which it is likely to be created?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) तथा (ख) टोहाना समेत सभी मंडलों व उप-मंडलों के बंटवारे हेतु, जिसमें विभिन्न वर्गों के कनेक्टान तथा सम्बद्ध सेवाओं का प्रसार भी सम्मिलित है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के अन्तर्गत सक्रिय विचाराधीन है। समस्त वितरण प्रणाली की समीक्षा के बाद इस विषय पर भीघ्र ही फैसला ले लिए जाने की संभावना है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

T.A. drawn by the Officers in the Home (CID) Department

448. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Home be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in the Home (CID) Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81, to-date?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

1979-80	1980-81
28134-55 रूपये	35015-45 रूपये (28-2-81 तक)

**T.A. drawn by the officers in Industrial Training
Department**

449. Sh. Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in the Industrial Training Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81, to-date?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): The requisite information in respect of Gazetted Officers is as follows:-

1979-80	1980-81 (upto 10.3.1981)
Rs. 30431.35 paise	Rs. 42554.31 paise

**T.A. drawn by the officers in the Medical Education
Department**

450. Sh. Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in the Medical Education Department on account of official tours during the year 1979-80 and 1980-81 upto-date?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि ₹ रूपयों में
1979-80	45703.39
1980-81	96248.60

T.A. drawn by the officers in the Institutional Finance and Credit Control Department

451. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in the Institutional Finance and Credit Control Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्ष 1979-80 एवं 1980-1981 (अब तक) संस्थागत वित्त एवं साख नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी दौरों के लिए यात्रा खर्च (यात्रा भत्ता) की सूचना निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रूपये
1979-80	3759.90

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

राज्य में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा विशेषकर हिसार में जुर्मों के अधिक होने संबंधी।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, मुझे सर्वश्री मंगल सैन, मूलचन्द मंगला, जय नारायण खुण्डिया और सर्वश्री मूलचन्द जैन ओर वीरेन्द्र सिंह तथा श्री कंवल सिंह, एम.एल.ए. साहेबान की ओर से प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की बिगड़ती हुई हालत और खासकर हिसार में क्राइम के बढ़ने के बारे में काल अटैन्शन में नोटिसिज प्राप्त हुए हैं। मैं इन्हें मन्जूर करता हूँ। पहले डा. मंगल सैन अपना नोटिस पढ़ दें।

डा. मंगल सैन: मैं सरकार का ध्यान प्रदेश में विशेषतः हिसार में हुई दिन दहाड़े डकैतियों, छुरेबाजी व हत्याओं की ओर आकृष्ट करनार चाहता हूँ। दिनांक 18-3-81 को हिसार नगर निवासी श्री चूड़िया मल टाईपिस्ट के घर से श्री सती कुमार, जो कि उसके पास काम करता था, उसे बुलाकर कुछ लोगों द्वारा चाकुओं से छेद डाला गया जिसके कारण उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद बाजार में आने जाने वालों को सरेआम लूटा गया तथा घायल किया गया।

अराजकता, गुण्डागर्दी, छुरे की नोंक पर लोगों को लूटन की घटनाएं इन्हीं हत्यारों ने कई सप्ताहों से प्रारंभ कर रखी है। जिला हिसार की पुलिस तथा प्रशासन सर्वथा विफल रहा है। जिसके परिणामस्वरूप उन हत्यारों के हौंसले बढ़ जाने के कारण उपरोक्त दुःखदाया एवं हृदय को दहला देने वाली घटना घटी। सारे प्रदेश में प्रायः और हिसार में विशेषतः जनता में रोश एवं भय व्याप्त है। कई दिनों तक लोगों ने हड़ताल भी किए रखा। अतः हम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान सामान्य प्रशासन की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं तथा सरकार से हमारा आग्रह पूर्वक कहना है कि इस मामले में सदन को वक्तव्य दे कर विश्वास में ले।

स्पीकर साहब, जिस दिन यह वाक्या हुआ था उस दिन मुख्य मंत्री जी वहां पर गए हुए थे। इनको सारे हालात के बारे में मालूम हैं यह बात पहले भी इनके नोटिस में लायी जा चुकी थी लेकिन इन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण एक गरीब नौजवान श्री सती प्रकाश कुमार मारा गया। सारे प्रदेश में इस तरीके से दिन प्रतिदिन भय व्याप्त होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में अपना जवाब दे।

(इस समय सर्वश्री कंवल सिंह और मूलचन्द जैन अपना अपना नोटिस पढ़ने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker: Both the Call Attention Motions have been clubbed together and either of you, may read out the motion.

श्री मूल चन्द जैन: अच्छा जी, यह पढ़ देते हैं।

श्री कंवल सिंह: मैं सदन का ध्यान अत्यावश्यक लीक महत्व के इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ कि राज्या में कानून तथा व्यवस्था की सामान्य स्थिति के बारे में सरकार द्वारा किए गए दावों के उल्टे वास्तव में प्रतिदिन सारे राज्य में दुःखदायी घटनाएँ हो रही हैं। कुछ सप्ताह पूर्व दिन दहाड़े छुरेबाजी तथा छुरे की नोक पर लोगों को लूटने की घटनाएँ हिसार भाहर में हुईं। इस लाकानूनों से जनता बहुत भयभीत हो गई तथा मामला प्राधिकारियों के पास उठाया गया। इन सब दुर्घटनाओं के समाचार स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रेस में प्रकाश में लाए गए।

होली के त्यौहार से दो दिन पहले जब लोग इस खुशी तथा प्रसन्नता के त्यौहार को मनाने के लिए तैयार हो रहे थे तो नई दुर्घटनाओं ने भाहर के भ्रान्तिमय लोगों को घेर लिया। एक वकील के टाईपिस्ट को जब उसने धमकी मानने से इंकार कर दिया तो उसकी छूरा मार कर हत्या कर दी गई। एक अन्य व्यक्ति अस्पताल में गंभीर अवस्था में है। एक टैक्सी ड्राइवर को भाहर से बाहर ले जाया गया तथा नृसिंहा पूर्ण उकी हत्या कर दी गई। सिनेमा हाल में एक समूह की उपस्थिति में एक स्त्री की बालियों

को उसके कानों से बाहर खींचा गया जिससे उसके कान फट गए। कई दुकानदारों को छुरे की नोक पर लूटा गया है। भाहर की सारी आबादी को जीवन तथा सम्पत्ति का भ्या बना हुआ है। पुलिस इस गुंडा गंदी तथा लाकानून को रोकने में सर्वथा विफल रही है। इसके अलावा सभी गुंडे खुले तौर पर यह दावा करते हैं कि वे भाहर को बिना रोक टोक के चम्बल घाटी में बदल देंगे। प्रशासन की विफलता के विरुद्ध भाहर में भारी रोश व्याप्त है। भाहर में गत तीन दिनों से पूर्ण हड़ताल है तथा सरकार के निष्प्रभाव तथा इस गुंडागंदी के पीछे राजनैतिक महत्व वाली व्यक्तियों का हाथ होने के विरुद्ध मुख्य मंत्री का पुतला जलाया गया।

वकीलों के एक जलूस ने यह आरोप लगाते हुए डी. आई.जी. को खुले तौर पर यह चुनौती दी कि भाहर के थाने का तीस हजार रूपस मास पर नीलामी की जा रही है। श्रीमान जी राज्य के लोगों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है तथा सदन की इस ओर तुरन्त दखल देने की आवश्यकता है। इसलिए आप से निवेदन किया जाता है कि मेरे प्रस्ताव का स्वीकृत किया जाए तथा सदन को इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाए ताकि लोगों की वास्तविक तकलीफों को सदन के सामने लाया जा सके तथा सदन उन की तकलीफों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए।

श्री मूल चन्द जैन: मैं सदन का ध्यान अत्यावश्यक लीक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिसार भाहर में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां पर गत चार दिनों से लगातार पूर्ण हड़ताल चल रही है। एक सती 1 कुमार की हत्या तथा कुख्यात राहजनों और हत्यारों द्वारा कई अन्य व्यक्तियों को पहुंचाई गई गम्भारी चोटों के कारण वहां पर होली तथा फाग जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार भी नहीं मनाया गया। 18 तथा 19 मार्च की रात के मध्य उन्होंने कई राहजनियों की जिनमें उक्त सती 1 कुमार कत्ल कर दिया गया तथा कई अन्य व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई उसी गैंग ने इस वर्ष फरवरी के अन्तिम सप्ताह में राहजनों के 7,8 मामले किए। हिसार भाहर के निवासी होने के बावजूद हिसार पुलिस ने दोशियों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न एि जाने तथा खुफिया तौर पर अपराधियों का साथ देने के विरुद्ध हिसार बार ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया तथा लगभग 300 वकीलों ने एक खामो 1 जलूस निकाला। भाहर में भय का वातावरण छाया हुआ है। अधोहस्ताक्षरी को इस संबंध में हिसार बार के प्रैजिडेंट द्वारा भेजा गया तार इस प्रकार है:—

‘हिसार भाहर में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति निम्नतम स्तर पर है। हत्याएं राहजनी तथा स्त्रियों पर आक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है, जनता बहुत उतेजित है। भाहर में पूरी हड़ताल है।’

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब,

Mr. Speaker: Ch. Kanwal Singh Ji, you have read out your Call Attention Motion and that will be replied by the Government. Now please sit down.

श्री कंवल सिंह:

Mr. Speaker: Nothing will be recorded which is not in the Call Attention Motion.

श्री कंवल सिंह:

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): स्पीकर साहब, इसका जवाब कल दे दँगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह वाका हुआ, उस दिन मैं वहां मौके पर गया। जो सती कुमार मारा गया है, उसके घर भी गया और हस्पताल में भी गया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जिन-जिन पुलिस कर्मचारियों का दोश नजर आया उनको सस्पेंड किया गया है। वहां पर एस.एच.ओ., यानी इन्स्पेक्टर को मौके पर ही सस्पेंड किया गया और इसके साथ ही साथ एक हवलदार और दो सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है। इसका पूरी डिटेल में जवाब कल होम मिनिस्टर साहब दे दँगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मेरी गुजारि है कि अभी चौधरी कंवल सिंह ने

अपने मोान को पढ़ने के बाद कुछ बातें कहीं हैं और आपने उनको एक्सपंज करने का हुक्म दे दिया है। किसी बात को एक्सपंज करने के लिए रूल 116 है। इन्होंने यही कहा था कि कोई खास व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति का नाम लिया गया है या नहीं। इनका कहना यही है कि उस व्यक्ति को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। पहले जिस समय पोसवाल साहब होन मिनिस्टर हुआ करते थे उस आदमी का नाम उस समय से ही 'बस्ता बे' में दर्ज हैं।

Mr. Speaker: Pleased sit down. I have understood your point of order.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठ जाइये। जो मोान इन्होंने दिया है, केवल उसी को पढ़ सकते हैं। अगर उसके बासद कोई किसी पर व्यक्तिगत इल्जाम लगाये that can only be done with the permission of the Speaker. After it is given to me in writing and I have given the permission he may speak these things. Otherwise any personal allegation cannot be levelled.

Sh. Verender Singh: He has not levelled any personal allegation.

Mr. Speaker: Whether a person is named or is pin-pointed by designation, the levelling of allegations is not permissible. इन्होंने मुख्य मंत्री जी के बारे में और कुछ डी.आई.

जी. के बारे में भी कहा। It should be given in writing and it is only after the permission of the Chair that it can be read out. That is the procedure but it has not been adopted. That is why I have ordered for its not being recorded.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस की ओर दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने जो काल अटैन्डान्स का नोटिस दिया था, वह इन्होंने पढ़ कर सुना दिया है। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस गुंडागर्दी के पीछे राजनैतिक महत्व वाली व्यक्तियों का हाथ होने के विरुद्ध मुख्य मंत्री का पुतला जलाया गया। यानी लोग वहाँ पर इतने नाराज थे कि उन्होंने मुख्य मंत्री का पुतला तक जलाया।

श्री अध्यक्ष: जो कुछ काल अटैन्डान्स में था, वह तो इन्होंने पढ़ दिया, वह मैंने बिल्कुल भी एक्सपंज नहीं किया है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। श्री कंवल सिंह ने कहा कि प्रदेस के अन्दर

श्री अध्यक्ष: जो मैंने एक्सपंज किया है, क्या आप उसके बारे में प्वायंट आफ आर्डर उठा रहे हो ?

चौधरी गंगा राम: मैं यह कह रहा था कि कुछ गुंडों को मिनिस्टर्ज और हाई आफिसर्ज का संरक्षण प्राप्त है।

Mr. Speaker: No further discussion is allowed and nothing will be recorded.

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, यह फोटो और बारे एसोसिएशन के रैजोल्यूशन की कापी मैं हाउस की टेबल पर रखना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: Kindly bring it in my Chamber. I will examine it and if I admit, then these can be placed on the Table of the House.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था, उसका क्या बना है ?

श्री अध्यक्ष: वह तो अभी गवर्नमेंट को कमेंट्स के लिए भेजा हुआ है। मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, वह रिजेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वह बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला है।

श्री अध्यक्ष: मैंने उसे गवर्नमेंट को कमेंट्स के लिए भेजा है और कहा है कि चार दिन में मुझे अपने कमेंट्स दें। आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए मेरे चैम्बर में आकर बात कर लें या सैक्रेट्री साहब से इस बारे में पूछ लें। मैं विधान सभा की कोई चीज सीक्रेट नहीं रखता।

श्री भले राम: सर, मैंने सैक्रेट्री साहब से पूछा था कि 4 दिन कब पूरे होते हैं ?

श्री अध्यक्ष: आपको उन्होंने बताया था कि 27 तारीख तक उसका जवाब आ जायेगा। गवर्नमेंट का जवाब आने के फौरन बाद मैं उस पर फैसला ले लूंगा।

नेमिंग आफ मैम्बर

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मेरा और श्री हीरा नन्द आर्य का भी एक काल अटैन्डान्स मोडान था

Mr. Speaker: I have disallowed that as this is a matter of ordinary implementation of law and order. Nothing about it will be recorded.

Ch. Ganga Ram: Speaker Sahib *****

Mr. Speaker: Please sit down, otherwise I will name you.

Ch. Ganga Ram: Speaker Sahib *****

Mr. Speaker: Ch. Ganga Ram, please sit down.

Ch. Ganga Ram: Speaker Sahib *****

Mr. Speaker: Mr. Ganga Ram, I will name you.

Ch. Ganga Ram: Speaker Sahib *****

Mr. Speaker: All right, I name Ch. Ganga Ram.

Ch. Ganga Ram: Speaker Sahib *****

Mr. Speaker: I name Ch. Ganga Ram. He may please wiht draw from the House.

(The hon. Member did not withdraw but continued speaking)

Mr. Speaker: Remove him.

(At this Stage the Serjeant-At-Arms went to the hon. Member who then escorted by the Serjeant-At-Arms left the House)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैन् इन मो इन मैडिकल कालेज रोहतक के बारे में था। यह बड़ा ही इम्पोर्टेन्ट मसला है, वहां पर बहुत बुरी हाल है

Mr. Speaker: A similar motion about the Medical College Rohtak was moved by Sh. Har Swarup Bura. That was admitted and replied. Some question were also answered on that.

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, वह मो इन तो सिविल हस्पताल के बारे में था जबकि मेरा काल अटैन् इन मो इन मैडिकल कालेज रोहतक के बारे में है।

Mr. Speaker: Then I will re-examine it.

चौधरी संत कंवर: धन्यवाद, सर।

वाक आउट

श्री अध्यक्ष: अब वर्ष 1981-82 के बजट पर जनरल डिस्कान फिर शुरू होगी। श्री अजीत सिंह कल बोल रहे थे, वे अपनी स्पीच जारी कर सकते हैं।

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मेरी एक हम्बल सबमिशन थी। ला एण्ड आर्डर के बारे में पोजीशन यह है कि कई वारदातें तो गुंडे करते हैं जिसकी वजह से ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब होती है और कई बार पुलिस द्वारा लोगों के साथ ज्यादती की जाती है उस वजह से भी ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है

Mr. Speaker: I have disallowed it. I would request the hon. Member not to speak on it.

Sh. Ran Singh Mann: Speaker Sahib -----

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.,

श्री रण सिंह मान: मैं फिर ऐज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करता हूँ।

(इस समय श्री रण सिंह मान सदन से वाक आउट कर गये।)

श्री अध्यक्ष: बजट सेशन के अन्दर एक अपरच्युनिटी नहीं, 50 अपरच्युनिटीज मिलती हैं जिस वक्त ला एण्ड आर्डर पर डिस्कान की जा सकती है। क्योंकि हिसार का मामला ऐसा था जिसके बारे में मेरे पास 8-10 एम.एल.ए. साहेबान की तरफ से

नोटिस आया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसाके एडमिट कर लिया जाये। लेकिन अगर एक इन्सीडेंट किसीस गांव में हो जाता है तो that is a matter of normal enforcement of law and order. It does not form the basis of a call attention motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान की तरफ अगर गुंडों की वजह से खराब होती है तो दूसरी तरफ पुलिस की ज्यादाती की वजह से भी खराब होती है इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप अपने फ़ैसले पर दोबारा विचार कर लें।

Mr. Speaker: You can come to my Chamber and discuss it with me. I will give you a full hearing.

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now the House will resume discussion on the Budget for the year 1981-82.

श्री मूल चन्द जैन: बजट पर डिस्क ान के बारे में मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। मैम्बर, जरा ज्यादा बोलना चाहते हैं इएलिये आप टाईम की पाबन्दी लगा दें। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि मुझे पता चला है कि आज सी.एम. साहब की तरफ से लन्च है। सै ान बराबर चलता रहे और कुछ लोग बीच बीच में जाकर खाना खा आयें। इससे डिस्क ान करने के लिए ज्यादा टाईम मिल जायेगा तथा ज्यादा मैम्बर बोल सकेंगे।

Mr. Speaker: I will have to take the sense of the House.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, रिपोर्टर्ज, वगैरह बैठे हैं, इन्होंने भी लन्च करना होगा, इनको दिक्कत आयेगी। आप डेढ़ घंटे की बजाये एक घंटे की ब्रेक कर लें।

श्री अध्यक्ष: पहले तो डेढ़ से अढ़ाई बजे तक ब्रेक करने का विचार था लेकिन उस समय डाक्टर मंगल सैन की तरफ से रिक्वैस्ट आने पर दूसरी सिंटिंग तीन बजे करने का फैसला हुआ था।

There are various proposals before the House and I want to take the sense of the House in that regard. The first proposal is कि 15 मिनट से टाइम 10 मिनट रिड्यूस कर दिया जाये ताकि ज्यादा मैम्बर बोल सकें। 10 मिनट से, 12 मिनट तक तो एकसैप्टेबल हो सकता है लेकिन 15 मिनट एकसैप्टेबल नहीं होगा। अगर हाउस एग्री करता है तो 12 मिनट के बाद मैं दूसरे मैम्बर को काल अपोन कर लिया करूंगा ?

आवाजें: ठीक है जी।

Mr. Speaker: The second proposal is that the sitting may go on without lunch breack till the business fixed for today is completed.

The other proposal is that the House may be adjourned at 1.30 p.m. to meet again for the second sitting at 2.30 p.m.

कुछ आवाजें: ठीक है जी एक घंटे का ब्रेक कर लिया जाए।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, पहले भी यही प्रैक्टिस रही है कि हाउस कंतिन्यूस चलता रहता है और मैम्बर साहेबान खाना खाते रहते हैं।

कुछ आवाजें: स्पीकर साहब, एक घंटे का ब्रेक रख लें।

श्री अध्यक्ष: बात यह है कि बजट पर डिस्क इन डेढ़ बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद एजेंडे के मुताबिक दूसरी सीटिंग तीन बजे होनी है। बजट पर डिबेट चल रही है उस पर 12.30 बजे डिस्क रूान कन्क्लूड करूंगा क्योंकि उसके बाद वित्त मंत्री महोदय ने भी जवाब देना है। He will start replying at 12.30 p.m. sharp. उसके बाद जैसा हाउस चाहे लंच का आधा घंटा रख लें या एक घंटा रख ले लेकिन इस तरह से जो दूसरी सिटिंग का टाईम बढ़ेगा वह डिमांड्स के लिए होगा।

आवाजें: लंच ब्रेक एक घंटे का ही काफी होगा।

श्री अध्यक्ष: तो यह फैसला हुआ है कि एक घंटे के लिए लंचा ब्रेक होगा और हरेक मैम्बर को अब बोलने के लिए दस मिनट मिलेंगे।

चौधरी अजीत सिंह (बेरी): स्पीकर साहब, वित्त मंत्री श्री खुरीद भाई ने जो बजट इस हाउस में पेश किया है, मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ:-

सोचा था हर गुत्थी को खोलोगे, सुलझाओगे,
किसे पता था तुम कुर्सी की खातिर यूँ बिक जाओगे,
चांद ईद का एक साल में एक बार आ जाता है,
हमें पता है पांच साल तुम भावल नहीं दिखलाओगे ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय फरमाते हैं कि हमने टैक्स कोई नहीं लगाया, उसके बारे में आगे सुनिए:-

टैक्स बजट में नहीं लगाया, तो भी कुछ अहसान नहीं,
बाद बजट के नोंच-नोंच कर लोगों को तुम खाओगे,
मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दो इस जनता को,
घी के मटके लुढ़क-लुढ़क कर कब तक आगे
बुझाओगे ।

कल स्वामी आदित्यवेदी ने बोलते हुए यह कहा था कि हमारी सरकार ने तपरीवासियों के लिए और विमुक्त जातियों के लिए बड़ा दिल खोलकर इस बजट में प्रावधान किया है। स्पीकर साहब, तपरोवासी की आज जो हालत है वह मैं बताना चाहता हूँ।

एक तपरीवासी सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। बजट आने के बाद उसने सोचा कि बजट में काफी छूट दी गई होगी और अब सारी चीजें बाजार में सस्ती मिलेंगी, अब तो मौज हो गई। वित्त मंत्री ने वायदा किया था कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और सब चीजें अब बाजार में सस्ती मिलेंगी। जब उसने दुकान से सारा सामान देने हेतु कहा दुकानदार ने उससे कहा कि सामान का 118.10 रूपया बनता है। तपरीवासी ने कहा कि मेरा तो केवल 18.10 रूपये हैं। इस पर दुकानदार ने कहा कि 18.10 रूपये में चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं। दुकानदार ने बताया कि तुमने चार किलो चावल खरीदा है उसकी कीमत पांच रूपये ली के हिसाब से बीस रूपये बनती है। पांच किलो दाल की कीमत पांच रूपये किलो के हिसाब से पच्चीस रूपया। छः किलो गेहूँ अढ़ाई रूपए प्रति किलो के हिसाब से पन्द्रह रूपये। दो किलो तेल चौदह रूपये के हिसाब से अठारह रूपए। चार किलो भाकर सात रूपये चालीस पैसे के हिसाब से 29.60 रूपए। एक नमक की थैली की कीमत पचास पैसे है। तपरीवासी के पास इतने रूपये नहीं थे इसलिए वह उस सामान को नहीं खरीद सका। उसने सामान वही छोड़ा और वापिस चल दिया। जब वह अपने बच्चों के लिए खाने के सामान की कोई व्यवस्था नहीं कर सका तो, उसने रास्ते में एक नमक की थैली और एक भूगडे की थैली खरीदी और उसको लेकर घर पहुंचा। घर पर बच्चे सोच रहे थे कि आज हमारे पिता जी बहुत सा सामान लेकर आएंगे, हमारे दुःखों की अन्धेरी रात आज कटने वाली है और सुख का सवेरा आने वाला है। उस

तपरीवासी ने नमक की थैली और भूगड़े की थैली और भूगड़े की थैली बच्चों को दे दी और उनसे कहा कि इन भूगड़ों में नमक लगाकर अपनी भूख मिटा लो। उन छोटे बच्चों ने उस थैली को फाड़ लिया। स्पीकर साहब, उस थैली में से छोटे छोटे कागज के टुकड़े निकल जिन पर लिखा था गरीबी हटाओ बजट, टैक्स फ्री बजट। उस तपरीवास ने वे कागज के टुकड़े बच्चों के हाथ से ले लिये और उन पर्चियों को, जिन पर टैक्स फ्री लिखा था, फाड़ दिया और बच्चों को कहा कि इन टुकड़ों को इस नमक में घोल कर पी जाओ। स्पीकर साहब, आज यह हालत हर गीरब आदमी की है जिसको इस सरकार ने झूठे नारे देकर बहकाया है और कहा है कि हम तुमको मकान देंगे, सस्ती चीजें देंगे लेकिन इस बजट को पढ़ने के बाद हर आदमी को असलियत का पता लग गया है। स्पीकर साहब, बजट स्पीच के 21 पेज पर इन्होंने लिखा है कि संचार व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हर गांव को सड़क से जोड़ देंगे। स्पीकर साहब, हालत यह है कि अभी बेरी हल्के का तीन चार महीने पहले चुनाव हुआ था। उस समय मंत्री जी नारे लगाते फिरते थे कि हर जगह सड़कों का जाल फैला देंगे। बेरी हल्के में अच्छे, भाफीपुर, मलिकपुर और पहाड़ीपुर चार गांव पड़ते हैं। इलैक्शन के दिनों में इस सरकार ने उन रूट्स पर केवल वॉटें लेने के लिए बसें चला दी और बाद में वे बन्द कर दी। ये इस सरकार के केवल थोथे वायदे हैं। कहीं भी सड़क संचार व्यवस्था ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, सरकार ने बजट स्पीच के पेज 22 पर लिखा है कि हरियाणा पर्यटक विभाग और निगम का

1.25 करोड़ रुपये का योजना आवंटन है। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस पर्यटक निगम को खोलने की क्या आवश्यकता थी जब प्रदेशों के अन्दर अन्नदाता किसानों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, किसानों के बेटों को खाने के लिए दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता है ? जिस प्रदेशों में बड़ी बड़ी अटटालिकाओं को बनाने वाले कारीगरों के पास रहने के लिए झोपड़ा न हो और जिस प्रदेशों में कपड़ा बनाने वाले कारीगरों के पास पहनने के लिए कपड़ा न हो ऐसी हालत में मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि पर्यटक निगम को 1.25 करोड़ रुपये देने की क्या आवश्यकता है ? यही रूपया अगर किसानों की मदद के लिए खर्च किया जाता, मजदूरों की मजदूरी जो इस समय 8.45 रुपये है उसको बढ़ाकर सोलह रुपये की जाती तो कितने लोगों का भला होता। इसी रूपये से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाता तो स्टेट का कितना भला होता। अयाजी के लिए यह रूपया खर्च किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, 22 पेज पर इन्होंने लिखा है कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ायेंगे। आज सब को पता है कि देशों के अन्दर शिक्षा की क्या हालत है। हमारे प्रदेशों में कितने ऐसे स्कूल हैं जो केवल टाट पट्टी के स्कूल हैं। छोटे बच्चों के पास एक टूटी स्लेट होती है और उसी को लेकर वे स्कूल जाते हैं उनको ठीक शिक्षा देने की इस सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है।

स्पीकर साहब, पेज 19 पर इन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चालू की जा रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम रोजगार नहीं देंगे। रोजगार न देकर बचत करेंगे। ऐसा इन्होंने बजट स्पीच में कहा है। एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ रोजगार न देकर पैसे की बचत करेंगे। ये दोनों बातें कन्ट्राडिक्टरी हैं। स्पीकर साहब, कल मैं रोहतक से आ रहा था तो दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि 10 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इनका जिम्मेदार, टाटा बिरला की सरकार, इन्दिरा भजन लाल की सरकार। स्पीकर साहब, एक तरफ तो ये लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार न देकर पैसे की बचत करके घाटे को पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को इस बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसा बेरोजगारी दूर करने के लिए देना चाहिए। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि बिक्री कर में वृद्धि से और कंसाइनमेंट टैक्स लगाकर हम इस घाटे को पूरा करेंगे। स्पीकर साहब, तीन चार दिन पहले चौधरी उदय सिंह दलाल के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि जिन लोगों से एक लाख रूपए या इससे ऊपर सेल्ज टैक्स देय है ऐसे लोगों की तरफ 11.30 करोड़ रूपया बकाया है और साढ़े नौ करोड़ रूपये के करीब सेल्ज टैक्स का बकाया उन व्यापारियों की तरफ है जिनसे एक लाख रूपए से कम की राशि देय है। इस तरह से लगभग 21 करोड़ रूपये की राशि ऐसी बनती है जोकि अभी व्यापारी लोगों से ली जानी है लेकिन

इस बजट में उस राशि को रिकवर करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कोई प्रोवीजन नहीं रखा है।

11.00 बजे

दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे प्रान्त के किसान, मजदूर और हरिजन व दूसरे तबके के जो लोग हैं, वे अगर केवल 200-200 रूपया तकावी का सरकार को वापिस नहीं करते तो इसके लिए उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। यह कितनी भार्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, आगे चलकर इन्होंने अपनी बजट स्पीच में यह लिखा है कि हमने किसानों को बड़ी बड़ी रियाते दी हैं ओर कृशि के क्षेत्र में भी उनकी बड़ी मदद की है। कल स्वामी जी भी कह रहे थे कि हम 82 परसैन्ट किसानों के लिए कृशि के क्षेत्र में सब सहूलियतें दे रहे है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह एक तरह का किसानों और गरीब मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय है, उनके साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। किसान जो अपने खेत के अन्दर पैदावार करता है, उसको उसकी मेहनत का सही दाम नहीं दिया जाता है। आलू मक्का वगैरह जो किसान पैदा करता है, उसको तो अपने आलू का भाव 2 रूपये प्रति किलों के हिसाब से मिलता है लेकिन उसी आलू के चिप्स बाजार में 20 रूपये किलो मिलते हैं। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उत्पादक के साथ यह भाशण की नीति क्यों बरती जा रही है ? किसान को आलू तो 20 रूपये का भाव लिया जाता है। तो यह जो 18 रूपये का फर्क है, इसको दूर करने का बजट में सरकार

की तरफ से कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है। (घंटी) मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से किसानों का भाषाण किया जा रहा है। फिर यह सरकार कहती है कि हम किसानों के बड़ हमदर्द हैं।

स्पीकर साहब, इससे आगे वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में यह कहा है कि सरकार की वाटर सप्लाई की स्कीमज बहुत उत्तम है। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में एक गुडडा गांव है। वैसे तो जब हम झज्जर से गुजरते हैं तो रास्ते में कई गांव ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर डेढ़ दो मील के अन्दर अन्दर कहीं पर भी लोगों को पीने का मीठा पानी नहीं मिलता है। क्या मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इन इलाकों के कुएं खुदवा कर टैंकियां बनवा दें। हमारी बहिनों को दूर दूर से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, जिनके पेट में 9-9 महीनों के बच्चे होते हैं, उन्हें दूर दूर जाने में काफी दिक्कत होती है। रात के अन्धेरे में तपती दुपहरी में और कड़कती सर्दी में उनको पानी के लिए जाना पड़ता है। यह हालत तो है सरकार की वाटर सप्लाई स्कीम की जो मैंने अभी बताया है। फिर सरकार कह रही है कि हम ने हर गांव में पीने के पानी की सुविधाएं लोगों को दी है। स्पीकर साहब, मैं तो यह कहूंगा कि यह जो बजट तैयार किया गया है यह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी हैं और गरीब आदमियों को राहत देने के लिए इससे कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए इस

बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, दोनों ही मर रहे हैं।
स्पीकर साहब, आखिर में मैं आपका धन्यवाद करते हुए व बजट
का विरोध करते हुए केवल चार लाइनें कह कर अपना स्थान
लूंगा:—

बजट बना है धनवानों का, गरीबों को कोई सरेकार
नहीं।

धनवाले ही पलेंगे बजट से, गरीबों का कोई उद्धार
नहीं।

आर्थिक विशमता और बेरोजगारी हटाने का कोई विचार
नहीं।

ऐसे भूखे सूखे बजट के रहते, चल सकती यह सरकार
नहीं।

धन्यवाद।

चौधरी गया लाल (हसनपुर—अनुसूचित जाति): अध्यक्ष
महोदय, इस समय सदन में वर्ष 1981—82 के बजट पर चर्चा चल
रही है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खडत्रा हुआ हूँ। अध्यक्ष
महोदय, यह कर हीन, गरीब परवर और एक आदर्श बजट है
जोकि हमारी सरकार ने पेश किया है। (विघ्न)

नेम किए गए सदस्य को वापिस बुलाना

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि आप कृपया चौधरी गंगा राम जी को हाउस में बुला लीजिए।

श्री अध्यक्ष: हां। बड़ी खुशी से उनको बुला लो।

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी गया लाल: अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे प्रदेश में सवा तीन लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की रेखा के नीचे रह कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने पिछड़े हुए लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, कई मूल भूत योजनाएं तैयार की हैं। आप देखें एक तरफ तो सरकार इतना कुछ कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, लोक दल तथा दूसरे विरोधी दल आरक्षण का सिलसिला खत्म करने के लिए कह रहे हैं और लोगों को भडत्रका रहे है। (गौर एवं व्यवधान) हमारी सरकार ने गांवों में रहने वाले 75 परसेन्ट लोगों के लिए 10 हजार के करीब मकान तैयार किये हैं। ये मकान छोटे तबके के लोगों को दिये जाएंगे। यह एक बड़ी ही सराहनीय बात हमारी सरकार ने की है। इसी से आप सरकार की अच्छी नीति का अन्दाजा लगा सकते हैं

कि सरकार गरीब लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ कर रही है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने दो जहार की आबादी वाले हर गांव में सहकारी स्टोरों की भी स्थापना की है, जिनके द्वारा गरीब लोगों को सस्ते दामों पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिल सकेंगी।

इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजन कल्याण निगम के द्वारा हरिजन लोगों को कर्ज देने का प्रबन्ध यिका गया है। पहली सरकार ने इस काम के लिए 2 करोड़ रुपया रखा था लेकिन चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने उस रकम को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। (तालियां) यहां तक भी किया कि जहां भी हमारे मुख्य मंत्री महरोदय जाते हैं, वहां पर हरिजनो को बाई हैन्ड ही चैक दिया जाता है ताकि वे लोग आगे की परे ानी से बच सकें। पहले चार छः महनी उनको परे ानी होती थी लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बहिन भाकुन्तला जोकि इस विभाग की राज्य मंत्री हैं वे मुख्य मंत्री महोदय के साथ जाकर सीमा जिलों में हरिजन लोगों को पैसा बांटती है। भैंस, बकरी और मुर्गियां वगैरह पालने ओर खरीदने के लिए भी कर्जा दिया जाता है ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए काफी व्यवस्था रखी है। वजीफा, किताबें और कपडों के रूप में सहायता देने की भी हरिजन बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। इससे जो गरीब बच्चा है, उसको

काफ़ी रियायत मिलती है। इसी तरह से आपको गरीबों के प्रति सरकार की नियत का पता चल जात है कि कितनी साफ़ है। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब हरिजनों के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सरकार ने काफ़ी पैसे का उपबन्ध अपने बजट में किया है। बाबू मूल चन्द जी कह रहे थे कि सरकार ने फूड फार वर्क स्कीम के लिए कोई पैसा नहीं रखा। वे बजट स्पीच का सफा 19 देखें उसमें ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उल्लेख किया गया। इसके तहत 25 हजार मीट्री टन अनाज और सामान की खरीद की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए डेढ़ करोड़ रुपये हमें केन्द्रीय सरकार से मिलने की सम्भावना है। इसके अलावा जहां पहले ग्राम पंचायतों की हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई थी उसके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारी सरकार ने हर ग्राम पंचायत को 20 हजार रूपए पंचायत भवन बनाने के लिए देने का फैसला किया है। पहले पंचायतों में झगड़ा होता रहता था क्योंकि सरपंच या तो अपने घर में पंचायत बुलाता था या किसीन अपने दूसरे आदमी के घर में बुलाता था। पार्टी बाजी के कारण विपक्ष के पंच वहां जा नहीं पाते थे। अब जब पंचायत घर बन जाएंगे तो यह सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो यह भी हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। इसी तरह सह पिछड़ी जातियों के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं इस सम्बन्ध में श्री जय नारायण जी ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें उन्होंने 4-5 मांगें रखी थी। हमारी

सरकार ने उन सब बातों को पूरा कर दिया है। पहले पिछड़ी जातियों के लिये जहां 2 या 5 परसेंट रिजर्वेशन हुआ करती थी अब उसे बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार से फीस माफी के लिए 3600 रुपये की वार्षिक आय को बढ़ा कर 4200 रुपये कर दिया गया है। पिछड़ी जातियों की डाक्टरी और इंजीनियरिंग लाइन में भी रिजर्वेशन रखी गई है। इनके लिए एक बोर्ड की स्थापना भी की गई है जिसके लिए दो करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इससे बैकवर्ड क्लासिफिकेशन के जो लोग बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिलेगा। यह गरीबी दूर करने का बहुत बढ़िया रास्ता है। इसी तरह से हमारा मेवात क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उसकी डिवेलपमेंट के लिए भी हमारी सरकार ने एक मेवात डिवेलपमेंट बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड ने उस क्षेत्र में कई तरह की फैक्ट्रीज स्थापित करना शुरू कर दिया है। यह भी एक बहुत अच्छा कार्य हमारी सरकार ने किया है। आज से पहले किसी भी मुख्य मंत्री या सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था कि हरियाणा में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो गरीबी की रेखा से नीचे है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। मेरे को आप डिमांड पर चाहे समय मत देना लेकिन अब समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो हाउस का फैसला है, आप एक मिनट और बोल सकते हैं।

चौधरी गया लाल: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेवात क्षेत्र को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड क्षेत्र घोषित करके एक बढ़िया काम

किया है इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेवात क्षेत्र की तरह हसनपुर और पलवल तहसील जो जमना के किनारे खादर में बसे हुए हैं, इनकी व्यवस्था भी वैसी ही है। मैं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस क्षेत्र को भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड क्षेत्र घोषित करें ताकि यह क्षेत्र भी जो आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ है दूसरे क्षेत्रों के बराबर आ सके। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय हमसरी सरकार ने 31 मार्च तक हर गांव को सड़के के साथ मिला कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। जो गांव 250 की आबादी से भी नीचे हैं उनको भी सड़क से मिलाने का प्रावधान रखा है। पहले जो लोग सड़क से वंचित थे, अब उनके लिए भी सड़क बनेगी। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने बसों की संख्या भी बढ़ा दी है। दो सौ के करीब और बसे चलाई जाएंगी जिससे लोगों को और सहूलियत मिलेगी। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने किसानों के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जो बड़ जमींदारों के खेतों में पक्के खाल बनेंगे उनको भी उसके लिए 50 प्रति ात की छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने बिजली और पानी की सहूलियत बढ़ाने के लिए 54 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च करने की व्यवस्था की है। सबसे बढ़िया जो कार्य हमारी सरकार ने किया वह यह कि गरीब परवर आरैर महापुरुश जो छोटू राम जी हुए हैं, उनकी जयन्ति चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने मनाई। (गोर) यह गरीब किसानों के लिए सबसे बढ़िया सरकार है। लोक

दल के भाइयों ने किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यह तो दल है। इन्होंने तो गरीबों को वोट भी नहीं डालने दिया। (गोर) (घंटी) आप बार बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं इतना ही कर कर अपना स्थान लेता हूँ।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात कही थी कि प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी, लोक दल और दूसरी पार्टियों को बुलाया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं वास्तव में हेराफेरी तो ये कर रहे हैं। (गोर)

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। चौधरी गया लाल जी जब बोल रहे थे तो इन्होंने लोक दल को दल कहा। यह भाब्द एक्सपंज होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अगर ऐसी कोई बात आई है तो उसे एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री लहरी सिंह मेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी गया लाल जी ने जो भाब्द कहा है वह गलत है (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: वह मैं पहले ही एक्सपंज करवा चुका हूँ, आप बैठिये।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट एक फाईनैस मिनिस्टर ने पे 1 किया है उससे सारा प्रदे 1 सारे एम.एल.एज. चाहे वे विरोधी पक्ष के हो चाहे ट्रेजरी बैंचिज के हो, यह उम्मीद लगाए हुए थे कि एक किसान का बेटा और इनटैलीजेंट आदमी बजट पे 1 करने लग रहा है, उससे जरूर कुछ राहत मिलेगी। हम भी बड़ी खुशी के साथ उस दिन यहां हाउस में आए थे कि चौधरी खुरीद अहमद जी इस बजट के अन्दर गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए और किसानों के लिए कुछ करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी और उनको कैबिनेट के दूसरे वजीर गरीब लोगों के खिलाफ हैं परन्तु हमने चौधरी खुरीद अहमद जी के बारे में यह सोचा था कि ये अपने दिमाग से, बजट के जरिये गरीबों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन बड़े सफसो के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने एक रूखा सूखा बजट पे 1 किया है। इन्होंने इस बजट स्पीच में खुद लिखा है कि यह एक रूखा सूखा दस्तावेज है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इनटैलीजेंट आदमी ने जो इस तरीके का बजट पे 1 किया है उससे हमें भाक होता है कि उनको तो सिर्फ यह बजट पे 1 करने के लिए खड़ा कर दिया गया लेकिन यह बजट बनाया किसी और ने है। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी गया लाल जी ने एग्रीकल्चर के बारे में हरिजनों के बारे में और किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा। हरिजनों के बारे में मैं एक बात कहना

चाहता हूँ कि आज उनकी क्या हालत है। हरिजनों को जो कर्जा दिया जाता है वह सरकार नहीं देती बल्कि हरिजन कल्याण निगम द्वारा दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरिजनों की हालत यह है कि यदि कोई हरिजन भैंस के लिए, मुर्गी पालने के लिए या सुआर पालने के लिए तीन हजार रूपया कर्जा ले लेता है और किसी बीमारी की वजह से मुर्गियां मर जाती हैं या भैंस का कटड़ा या कटड़ा मर जाता है तो वह अंडे या दूध कहा से बेचेगा और इस हालत में वह कर्जा कैसे वापिस देगा ? लेकिन उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। किसान अगर कर्जा वापिस नहीं दे पाता है तो रेवैन्यू एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, कितने अफसासे की बात है कि जो लोग एक एक लाख दो दो लाख, दस दस लाख और बीस बीस लाख रूपया टैक्स का नहीं दे रहे हैं उन पर सरकार कोई मुकदमा नहीं बना रही लेकिन दसूरी तरफ अगर कोई किसान 500 रूपए नहीं दे पाता तो उसको जले में बन्द कर दिया जाता है। एक गुगन सिंह नाम के किसान ने 500 रूपये गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए कर्जा लिया था जोकि किसी कारणवत् वापिस नहीं दे सका। उसको हांसी के तहसीलदार ने पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। उस आदमी ने भार्म की वजह से रात के समय में जेल में फांसी लगा ली। इससे बढ़ कर भार्म की बात सरकार के लिए ओर क्या हो सकती है ? डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि गुण्डे आदमियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि करनाल में

एक आदमी उस आदमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास कर रखा है। (गोर एवं विघ्न)

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जो आदमी इस हाउस का मैम्बर नहीं है उस पर एलीगे इन लगाना उचित नहीं। चौधरी संत कंवर जी ने आउट साइडर पर जो एलीगे इन लगाया है, वह एक्सपंज किया जाए। (गोर)

उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंग

निगम/बोर्ड के सभापति या सरकार के अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पदनाम से लगाए गए आरोपों का कार्यवाही से निकालने सम्बन्धी।

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members on the 19th March, 1981, Ch. Jai Narain Khundia, a member from the Opposition Benches referred to certain allegations of corruption etc. contained in a circular letter against the Chairma, Haryana Khadi & Village Industries Board. I ordered their expunction from the proceedings.

Smt. Sushma Swaraj, a Member from the Opposition Benches rising on a point of order enquired if allegations against the Chairman of a Corporation/Board or other functionary of the Government could not be made even by designation when the concerned Minister could make a

statement and explain the position with regard thereto in the House.

I reserved my ruling.

The practice in the Lok Sabha is as under:-

“The speaker has laid down the following procedure to be followed in dealing with allegations made against outsiders:”

1. No member shall be allowed to make an allegation against an outsider unless he has obtained the prior permission of the Speaker after giving advance notice thereof to the Speaker and the Minister concerned. Such notice shall give the name of the person concerned, the nature of the allegation against him and some evidence to show that there is a prima facie case.

2. Where a member makes an allegation in the House against an outsider without obtaining the prior permission of the Speaker, the same may not form part of the record of the House.

3. In the case of allegations made against Government officers, it will be for the Minister concerned to make a statement in the House, if he so wishes.

4. Where a representation from an outsider is substantiated by documentary evidence, the Speaker may in his discretion refer the matter to the Government or the Committee on Petitions for inquiry and report.”

The allegations made by Ch. Jai Narain Khundia were without obtaining the prior permission or previous intimation to the Speaker and the same were rightly expunged from the proceedings of the House by me.

In future, I hope the Hon. Members will follow the same practice/procedure.

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

कंवर राम पाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था कि जो आदमी हाउस का मैम्बर नहीं है उस पर जो एलीगे इन लगाया गया है वह एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य चौधरी संत कंवर ने जो एलीगे इन किसी आउट साइडर पर लगाया है, वह एक्सपंज कर दिया जाए। (तोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कोई एलीगे इन नहीं लगाया। मैंने तो हरि राम के बारे में यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस के खिलाफ रिट्रक्चर पास कर रखा है। (तोर)

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपके सामने खादी बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ इतना बड़ा एलीगे इन आया क्योंकि खादी

बोर्ड का चेयरमैन गवर्नमेंट ने अप्वायंट किया है और लाखों रूपए का गबन करने लग रहा है। खादी बोर्ड का चेयरमैन सारी स्टेट को खाने लग रहा है। (गोर एवं विघ्न)

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गिद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, यदि कोई मैम्बर आपकी रूलिंग को चैलें करे तो यह रूल के खिलाफ है। (विघ्न)

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह कहना है कि खादी बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ लाखों रूपए के गबन का एलीगे गन है। वह गवर्नमेंट का अप्वायंट किया हुआ चेयरमैन है। वह हरियाणा खादी बोर्ड को लूट कर खाने लग रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: गंगा राम जी आप बैठ जाएं। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं। (गोर एवं विघ्न) गंगा राम जी आप बैठ जाईए ? (गोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मै। आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं करता। मैं तो यह कहता हूँ कि खादी बोर्ड के चेयरमैन ने लाखों रूपये का गबन किया है। (गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जाईए। (गोर एवं विघ्न) गंगा राम

जी आप बैठ जाईए वरना मैं आपको नेम कर दूंगा। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने ऐलीगे न नहीं लगाया। मैंने तो यह कहा है चूंकि चौधरी भजन लाल जी कहते हैं कि मेरा गुण्डों से कोई ताल्लुक नहीं है इएलिये मैंने यह कहा था कि हरि राम नाम का आदमी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास कर रखा है (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, उस आदमी का नाम लेने से इनके पेट में दर्द होता है। ऐसे आदमी का नाम कहां नहीं लिया जाता। इन्होंने एक ऐसे आदमी को मार्किटिंग बोर्ड का मैम्बर और मालिक बना रखा है जोकि स्टेट को अपने पद के जरिये लूट रहा है, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल जी ने एक नया काम भुरू किया है। उस काम पर चौधरी खुर पीद अहमद जी ने अपनी बजट स्पीच में यह नहीं लिखा कि कितना खर्चा होगा। वह नया काम है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री का इतिहास लिखा जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश का इतिहास तो लिखा जाना चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री का इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर मुख्य मंत्री का इतिहास लिखना है तो उसमें यह लिखना चाहिए कि मुख्य मंत्री दलबदल कर आए हैं। एक नवम्बर, 1966 जब से हरियाणा प्रान्त बना है तब से हरियाणा का इतिहास लिखा जाना चाहिए। इससे सारा पता लग जाएगा कि किन किन मुख्य मंत्रियों के समय में हरियाणा प्रदेश

की तरक्की हुई, कौन मुख्य मंत्री हरियाणा को बनाने का काम करता था और कौन मुख्य मंत्री दल बदली करके हरियाणा को डूबोने का काम करता था जिस मुख्य मंत्री ने बार बार दल बदल कर सारे हरियाणे कानाम भारत भर में बदनाम किया है ऐसे मुख्य मंत्री का इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं। नाथपा झाकड़ी के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ और इस बारे में मैंने सवाल भी दिया था। अगर यह प्रोजैक्ट कम्पलीट हो गया तो हरियाणा में बिजली की कमी पूरी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने प्रावधान तो किया है लेकिन मुझे यह प्रोजैक्ट पूरा होता नजर नहीं आता। सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है क्योंकि नाथपा झावड़ी से बिजली लेने के बारे में जो समझौते पहले हुए थे, वे दो बार बदल दिये गये। इस प्रोजैक्ट से हरियाणा को जो बिजली मिलनी थी उसमे से 5 प्रति शत उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। इसके अलावा बजट में यह भी कहीं नहीं लिखा गया कि यह प्रोजेक्ट कितने दिनों के अन्दर कम्पलीट होगा। एक साल के अन्दर कम्पलीट होगा या 4 साल के अन्दर कम्पलीट होगा। कुछ न कुछ तो टाईम लिमिट होनी चाहिए कि इतने दिनों के अन्दर प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह मैं एम्पलायमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि वह बेरोजगारों को

मिटाने का इन्तजाम करेगी। एक तरफ तो लोगों को रोजगार देने के वायदे किये जाते हैं और दूसरी तरफ खुर शिद भाई कहते हैं कि नई भर्ती नहीं करेंगे। ये दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्टरी हैं और इस हिसाब से यह कंट्रोवर्शियल बजट साबित होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, खुर शिद भाई के वित्त मंत्री बनने के बाद हरियाणा के तीन हजार लड़के, जो सर्विसिज में पहले से लगे हुए थे, एक ही दिन में अपने रोजगार से हटा दिये गए। जहां तक कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, ठाकुरी बीर सिंह जी यहां बैठे नहीं हैं। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट में जो सेल्ज मैन भर्ती किए जा रहे हैं, उनमें सिर्फ दो ही कौम के लड़के भर्ती किए जा रहे हैं। यह मुख्य मंत्री के लिए बड़ी अशोभनीय बात है। इन्होंने सिर्फ दो कौमों को ही लिया, बाकी प्रदेश के गरीब लड़कों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। ऐसा करने से उनकी रोजगार मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दो कौमों के लड़के सिर्फ इसलिए लिये हैं कि वे इस कौमों के वजीर हैं। यह कहते हैं कि मैं सहकारिता महकमें का वजीर हूँ, इसलिए मेरी कौम के लड़के ही इस महकमें में लगेंगे। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं मुख्य मंत्री हूँ इसलिए मेरी कौम के लड़के आयेंगे और जो लोक दल से ताल्लुक रखते हैं उनका एक भी लड़का सर्विस में नहीं आएगा। इन्होंने चुनाव लड़ना है और चुनाव के दौरान जो लोग कौम का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि यह हमारे साथ नहीं है, इस आधार पर ये लोगों से वोट मांगते हैं। आज दूसरी कौमों के आफिसर्ज को तंग किया जा रहा

है। इनके द्वारा एक कौम या दो कौम का प्रचार करना बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं चौधरी मेहर सिंह राठी से कहना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके से कभी प्रदे 1 चल सकता है ? क्या किसी दूसरे प्रदे 1 में इस तरह से होता है कि एक दो कौमों के लड़के ही सर्विस में लिए जाएं ? चौधरी रिजक राम ने इस मुद्दे को उठाया था कि हरियाणा सरकार एक जाति विशेष को हर मामले में नजर अंदाज कर रही है। इसलिए उनको वजारत से निकला दिया गया। अब उन्होंने श्रीमति इंदिरा गांधी को मैमोरैडम लिख कर दिया है, उसमें क्या लिखा है, वह तो वही जानते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं रावी ब्यास के पानी के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकार ने बजट में लिख दिया कि 6 करोड़ रूपया रावी ब्यास के पानी को हरियाणा में लाने के लिए रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस रूपये को किस चीज पर खर्च करेंगे जब कि पंजाब सरकार नहर खोदने की इजाजत ही नहीं देना चाहती। हरियाणा सरकार ने पानी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकद्दमा किया और सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला देगा। अब उन्हें मालूम हो रहा है कि हरियाणा के हक में फैसला नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अन्दर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि फैसला अभी मत दो और तारीख पर तारीख देते रहो। यह रिकार्ड की बात है कि हरियाणा की तरफ से वकील ने कहा है कि फैसला मत दो। हमारी

पोलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भायद आप डिजीजन नहीं दे पाओगे, इसलिए इस फैसले को आप पोस्पोन कर दो। इस बात की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। (गोर) रोजाना तारीखें डलवाई जाती हैं और डिप्टी स्पीकर साहब, यह हरियाणा की जनता के साथ निरा धोखा है। जब तक लोक दल की सरकार नहीं आएगी तब तक रावी ब्यास का पानी हरियाणा में नहीं आ सकता। (व्यवधान) हमने अपने भासनकाल में जनता की सेवा करने के लिए ड्रेनेज खोदी, जमींदारों को पूरा पानी दिया और पूरी बिजली दी लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि लाखों रूपए के सौदे करके दूसरों की बिजली काट कर कारखानेदारों को दी हो। डिप्टी स्पीकर साहब, राठी साहब किसान का नाम लेते हैं, हरिजन का नाम लेते हैं। क्या इन्होंने किसान की तरफ और हरिजन की तरफ कभी नजदीकी से देखा भी है। आज किसान की क्या हालत है ? डिप्टी स्पीकर साहब, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बड़ी गंभीर है। मैं कलावड़ गांव की मिसाल देता हूँ। (घंटी) उस गांव में दो गुंडे गये। उन्होंने एक ब्राह्मण की लड़की के साथ रेप किया। उस मौके पर उस लड़की का भाई हाजिर था। वह 10-12 साल का लड़का था। वह भाग कर भाोर मचाता हुआ गांव में आया और कहा कि उसकी बहिन को गुंडे पकड़े हुए हैं। गांव के एक आदमी ने एक गुंडे को पकड़ा लेकिन उसने उस पर गोली मार दी। इस तरह इस हादसे में वह आदमी भाहीद हुआ। वे दो गुंडे थे। उनमें से एक को तो गांव वालों ने पकड़ लिया लेकिन दूसरे को पुलिस

आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो ला एण्ड आर्डर की आज यह हालत है। इसी तरह से एक औरत का बच्चा उठा लिया गया और उसके एवज में 25000 रूपया मांगा गया लेकिन पैसा न देने पर उस बच्चे का कत्ल कर दिया गया। जहां ला एण्ड आर्डर इस तरह खाब हो और सरकार हाउस में कहे कि ला एण्ड आर्डर बिल्कुल ठीक है, यह कितने अफसोस की बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी गया लाल जी ने चौधरी छोटू राम जी का जिक्र किया। चौधरी गया लाल जी को अपने मुंह से चौधरी छोटू राम जी का नाम नहीं लेना चाहिए था। चौधरी छोटू राम जी तो ऐसी हस्ती थे, अगर वे आज जिन्दा होते तो पाकिस्तान न बनता और पंजाब का बंटवारा न होता। चौधरी गया लाल को भायद पता नहीं, उनके हरिजन लीडर चौधरी चांद राम को ऊपर उठाने में चौधरी छोटू राम जी का ही हाथ था। जहां तक चौधरी छोटू राम की जयन्ती मनाने का सवाल है, वह सरकार ने नहीं मनाई, लोक दल ने मनाई है। चौधरी भजन लाल की सरकार जयन्ती नहीं मना सकती। जब लोक दल की सरकार बनेगी वही जयन्ती मनाएगी। इन भाब्डों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांव): डिप्टी स्पीकर साहब, 1981-82 का जो बजट सरकार ने रखा है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री साहब को और वित्त मंत्री साहब को मुबारिकबाद देता हूं कि इससे अच्छा बजट इस प्रदेश के लिए और कोई नहीं हो

सकता और न ही ऐसा बजट पहले कभी आया है। यह बजट प्रोग्रेसिव है, औरिण्टेड है और गरीब लोगों को राहत देने वाला है। इसकी डिटेल्स में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता लेकिन जो प्रोविजन एग्रीकल्चर के लिए फारेस्टे इन के लिए, वैटरनरी सर्विसिज के लिए और दूसरे महकमों के लिए किया गया है वह काबिले तारीफ है, इससे समाज के हर वर्ग को राहत मिलेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमेंट से छठी पांच साला योजना के लिए हमारे प्रान्त को फण्डज की जो एलोकेशन हुई है, उसका मुकाबिला हमारे देश का कोई दूसरा प्रान्त नहीं कर सकता। छठी पांच साला योजना के लिए हमें 1800 करोड़ रुपया दिया गया है और यह अमाउंट स्टेट की आबादी के लिहाज से और एरिये के लिहाज से तकरीबन दोगुना है। इसी तरह से 1981-82 के प्लान के लिए 290 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। यह भी बहुत अच्छी अमाउंट है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे विरोधी पक्ष के भाई डैफिसिट बजट होने के नाते कुछ टीका टिप्पणियां कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रोग्रेसिव बजट वही होता है जिसमें डैफिसिट होगा। हमारा डैफिसिट 37 करोड़ का है और हमारी सरकार का इरादा है कि इस डैफिसिट को टैक्स लगाकर पूरा नहीं किया जाएगा। इसको पूरा करने के लिए इकोनोमिक मैबर्ज उठाये जायेंगे, टैक्स इवेजन को रोकेंगे और सेल्ज टैक्स की रिकवरी करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, जो मसले तमाम देश के सामने हैं, वही हमारे प्रान्त के सामने हैं। एक एनर्जी का है, पावर का है और दूसरा पापुलेशन ग्रोथ का है। जहां तक एनर्जी की

कंजम्पान की बात है, यह देना और प्रदेना की उन्नति को बताती है। इस समय हमारे यहां पावर की भौटेंज है। लेने वाले ज्यादा हैं और सप्लाई कम है। इसके लिए मैं सरकार के सामने इस सदन में कुछ सुझाव रखूंगा। लाईन लौसिज हालांकि हमारे प्रदेना में सबसे कम हैं फिर भी मैं समझता हूँ कि इनको और कम किया जा सकता है, थैपटस को कम किया जा सकता है। नए प्रोजैक्टस जैसे नाथपा झाकड़ी ठै, वस्ट्रन यमुना हाइड्रो प्रोजैक्ट है, पानीपत और फरीदाबाद में थर्मल प्लांट्स की एक्सटेंशन का काम है, उनको सरकार प्रॉयरेटी देकर जल्दी से जल्दी पूरा करे। चाईनीज पैट्रन पर कौनाल्ज पर स्माल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्टस लगाए जाएं चाहे उससे हम 5 गांवों को बिजली दे सकें या 10 गांवों को बिजली दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को चाहिए कि जहां जहां भी हम अपने रिसोर्सिज को यूटिलाईज कर सकें, करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि पावर पूरी न मिनले की वजह से प्रोग्रैस में रूकमावट आती है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राईवेट एन्टरप्रन्योर्ज की भी मदद ली जाए तो कोई बुरी बता नहीं होगी। सोलर ऐनर्जी की यूटीलाइजेसन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा कदम हमारी सरकार को उठाने चाहिए। इस सिलसिले में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों पावर बोर्ड के इंजीनियर्स ने एक ऐजीटेसन किया था। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ताहै कि जो लोग अच्छी नौकरियों पर हैं, जो सोसाइटी में मिडल क्लास या अपर क्लास में हैं, वे भी

अगर एजीटे इन करें तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। इस एजीटे इन से स्टेट को जितना नुकसान हुआ है उसको गिना नहीं जा सकता। मैं यह चाहता हूँ कि एसैन्ट्रियल सर्विसिज करार देकर के इस तरह के लोगों को चाहे वे इंजीनियर हों, डाक्टर हों या कोई और वैलपेड आदमी हों, एजीटे इन करने का कोई हक नहीं होना चाहिए।

जहां तक पापुले इन ग्रोथ का सवाल है, इसे चैक करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर तमाम पार्टीज को सोचना होगा। क्योंकि इस सम्बन्ध में अगर कांग्रेस पार्टी कोर्ट कदम उठाती है तो चौधरी उदय सिंह दलाल और चौधरी गंगा राम जी की पार्टी उसका विरोध करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बारे में तमाम पार्टीज को सोचना होगा। इसके लिए हमें एक कंफ्रिहेंसिव ला बनाना पड़ेगा, अगर हम देना का भला चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कर्ज की माफी की बात इन्होंने कही। लेकिन मेरे ख्याल में कर्जा माफ करना कोई अच्छी प्रथा नहीं है। एक मु त अगर कोई कर्जा किन्हीं हालात की वजह से न दे सके तो उसकी कि तें तो हो सकती हैं लेकिन कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। इससे सारे सिस्टम में खराबी आ जाएगीं लेकिन रिकवरी का जो सिस्टम है, विशेष करके बैंकस की रिकवरी का, वह निहायत ही खराब है। मिसाल के तौर पर कोई कमर्शियल बैंक यदि 5 हजार रूपये लोन के ऐडवांस करता है तो उसको रिकवर करने के

दो सिस्टम हैं। एक तो जनरल सिविल ला के तहत रिकवरी हो सकती है। दूसरे हरियाणा ऐग्रीकल्चर क्रेडिट आपरे इन एंड मिसलेनियस प्रोविजन्ज (बैंक) एक्ट, 1973 के तहत रिकवरी हो सकती है। इन दोनों सिस्टमज के तहत 5 हजार रुपये एडवांस की रिकवरी की जो फिगर्ज बनती है, वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनरल सिविल ला के तहत कोर्ट फीस 870 रुपये लेकिन 1973 के एक्ट के तहत केवल दो रुपये होती है। इसी तरह से सूट फाईल करने से पहले की फीस जनरल सिविल ला के तहत 55 रुपये लेकिन 1973 के एक्ट के तहत निल है। साढ़े सात परसेंट के हिसाब से लायर्ज फीस जनरल सिविल ला के तहत 375 रुपये और दूसरे ला के तहत 55 रुपये बनती है। जनरल सिविल ला के तहत सारा खर्चा 1290 रुपये बैठता है जबकि 1973 के एक्ट के मुताबिक यह केवल 57 रुपये बैठता है। इसमें होता क्या है ? बैंक्स के मैनेजर्ज और दूसरे आफिसर्ज अपने कुछ लायर्ज को औबलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। (विघ्न) हमारी स्टेट के हाथ में यह बात नहीं है लेकिन हमारी सरकार की तरफ से सैन्ट्रल गवर्नमेंट को इस तरह का कोई पत्र जाना चाहिए कि जनरल सिविल ला के तहत रिकवरी बंद होनी चाहिए और 1973 के एक्ट के मुताबिक की जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि फरटाईल और इरीगेटिड लैंड की ऐक्विजि इन कानून द्वारा बंद कर देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐक्सपैन् इन भाहर के साथ ही हो। भाहर से एक

मील चार मील या पांच मील के फासले पर जहां कल्लर जमीन हो, बंजर जमीन हो, वह जमीन ऐक्वायर होनी चाहिए। इसके लिए बकायदा कोई ला हमारी सरकार को बनाना चाहिए और कम्पनसे उन भी एडिक्वेट होना चाहिए तथा टाईम पर मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि लोग चाहे कोर्ट से जीत जाएं, सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएं मगर सरकार उनको पैसा न दें। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, गुड़गांव, तहसील, सोहना का इलाका जो कि आपका हल्का है और पटौदी का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां न तो ट्यूबवैल है और न ही कैनल है। इसलिए गुड़गांव कैनल में से एक ब्रांच सहजादपुर के पास से या जहां से भी इंजीनियरिंग ठीक समझें वहां से, गुड़गांव तहसील के लिए उपलब्ध कराई जाए। इसी तरह से मसानी बैराज से पटौदी और फरुखनगर के लिए एक नहर होनी जरूरी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, भाहरों में जो अनअथेराइज्ड कालोनीज हैं उनको सर्वे आज तक नहीं हुआ। उनके सर्वे का काम बहुत जल्दी करवाया जाए क्योंकि वे लोग ऐसैन्टियल ऐमेनिटोज से, चाहे वे वाटर सप्लाई की हैं, पक्की सड़कों की हैं, या बिजली की हैं, वंचित न रहे। इस तरह की ऐमेनिटीज उनके लिए देना जरूरी है। इन भाब्डों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री और

अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रदे 1 के लिए बनाया है।

श्री देवी लाल (सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, 16 मार्च को वित्त मंत्री जी ने 1981-82 का जो बजट पे 1 किया है उसका विरोध करने के लिए मैं खडत्रा हुआ हूँ। यह विरोध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपोजी 1न बैंचिज पर बैठा हूँ बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें 50 करोड़ रूपये का घाटा दिखा गया है और कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जिससे सरकार की नियत पर हमें भाक होता है कि यह आगे चलकर टैक्स लगाएगी। मेरे कुछ भाई यहां कह रहे थे कि यह किसान विरोधी बजट है लेकिन मैं कहता हूँ कि यह केवल किसान विरोधी ही नहीं बल्कि इन्सान विरोधी बजट है। इसके लिए मैं मिसाल भी देता हूँ। इन्होंने अपने बजट में 19 करोड़ 20 लाख रूपए होम डिपार्टमेंट के लिए रखे हैं लेकिन सारी स्टेट में ला एण्ड आर्डर की जो हालत है वह सबके सामने है। हिसार, धरोंडा और सोनीपत में जो घटनाएं घटीं हैं उनसे सिद्ध होता है कि यह बजट इन्सान विरोधी बजट है। (विघ्न) सोनीपत में जी.टी. रोड पर दो डकैतियां पड़ी है। चंडीगढ़ में तो उनका पता लग गया लेकिन सोनीपत के एस.पी. को पता नहीं लगा। यही नहीं, मैं सरकार का ध्यान एक और घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। सोनीपत में एक जगह खरखौदा है। वहां तीन आदमियों के एक सिख परिवार को कत्ल कर दिया गया है। उनको केवल गोली ही नहीं मारी गई

बल्कि छुरों से भी मारा गया। एक एक आदमी के 40-40 छुरे लगे हुए थे। जिस आदमी के साथ यह घटना हुई, वह एक कांग्रेस (आई) एम.पी. के चचाजात भाई थे। मैं इस बजट को इन्सान विरोधी न कहूँ तो और क्या कहूँ। यह इतनी बड़ी ज्यादाती है इस का जवाब सरकार को देना चाहिए। तीन कत्ल हुए लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। पुलिस ने ऐसे ही लोगों को पकड़ लिया और असली मुलजिम अभी तक नहीं पकड़े गये हैं।

यह सरकार देहातों की बात करती है कि हमने देहातों की उन्नति के लिए पचास परसेन्ट पैसा रखा है। मैं आपके जरिए से अपने हल्के में बड़वासनी गांव को एक मिसाल देना चाहता हूँ। वहां पर इस सरकार ने साइफन बनाया था लेकिन वह इतना छोटा है कि जो फ्लड का पानी जमा होता है वह उसमें से पूरा नहीं निकलता है। साइफन छोटा होने के कारण सारा फ्लड का पानी आसपास के एरिया की जमीन में भर जाता है। चौधरी हरद्वारी लाल की अध्यक्षता में एक फ्लड कमेटी बनी थी उस वक्त भी इस विशय में जिक्र आया था। कमेटी ने उस साइफन के बारे में रिपोर्ट दी थी कि यह चौड़ा होना चाहिए परन्तु आज तक वह यों का यों ही है। अब पता नहीं लगता कि कौन सा महकमा यह काम करता है। उसको ड्रेनेज वाले करते हैं या नहर वाले करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ड्रेनेज वाले किसी भी ड्रेन को खोदा हुआ दिखा देते हैं और पैसा भी ले लेते हैं लेकिन असल में वहां पर कोई काम नहीं होता। इसी प्राकर से इस साइफन की पोजी न

है, वह आज तक नहीं बन पाया है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस साइफन को जल्द से जल्द बनाया जाये ताकि गांव फ्लड से बच सके।

दूसरी बात मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ जिसके बारे में किसी भी मैम्बर ने ध्यान नहीं दिखाया है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट का तहसीलदार जाता है और प्लॉट नीलाम करके आ जाता है। इस बारे में रूल यह है कि जब भी कोई आदमी मौके पर बोली दगा उसकी वहीं मौके पर पोज़े इन दे दिया जायेगा लेकिन इस सरकार के टाइम में पोज़े इन देना तो दूर रहा उन लोगों के प्लॉटों पर दूसरे लोग कब्जा किये बैठे हैं। सोनीपत के अन्दर ऐसी बहुत मिसालें हैं। कस्टोडियन, वक्फ बोर्ड और म्युनिस्पल कमेटी ये तीनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं, इन्होंने सैंकड़ों लोगों को तबाह कर रखा है। कस्टोडियन से प्लॉट लिया जाता है लेकिन उसको म्युनिस्पल कमेटी लीज पर दे देती है। ये तीनों डिपार्टमेंट सरकार के अदायरे हैं इनके बारे में फैसला होना चाहिए कि कौन सा प्लॉट वक्फ बोर्ड का है और कौन सा प्लॉट म्युनिस्पल कमेटी या कस्टोडियन का है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से एक और भी बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। सोनीपत में सी.आर.ए. कालेज है। यह बहुत बड़ा कालेज है। इसमें ज्यादातर देहता के लड़के पढ़ते हैं। वहां पर पिछले दिनों प्रबन्धक समिति का चुनाव हुआ

था। जो प्रबन्धक कमेटी बनी थी उसने रजिस्ट्रार सोसायटीज के पास चुनाव की कापी भेजी लेकिन वहां से एतराज लग कर वापिस चली गई कि यह इलैक्ट्रिक न गलत हुआ है। उसी प्रकार से डी.पी. आई. ने भी एतराज लगा कर वापिस भेज दिया कि इलैक्ट्रिक न गलत हुआ है। फिर न जाने रजिस्ट्रार को आप्रेटिव सोसायटीज के पास कितने पैस पहुंच गये। उस एतराज को ठीक कर दिया गया और उस बॉडी को मान लिया। इससे ज्यादा क्रॉस न और कोई नहीं हो सकती।

डिप्टी स्पीकर साहब, दो करोड़ 27 लाख रूपया सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए रखा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, भाहरों के अन्दर पानी और सीवरेज की बहुत बुरी हालत है। सरकार के चार डिपार्टमेंट काम करते हैं, इम्पूवमेंट ट्रस्ट, हुड्डा, म्युनिसिपल कमेटी और हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड, हुड्डा और इम्पूवमेंट ट्रस्ट अपनी जो कालोनियां बनाते हैं, उनमें सीवरेज सिस्टम चालू करके देते हैं लेकिन म्युनिसिपल कमेटी एरिया में सीवरेज नहीं डाली जाती है और न ही वहां पानी का प्रबन्ध किया जाता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास सारा नक्शा होता है। इन चारों डिपार्टमेंट्स को मिल कर सीवरेज डालनी चाहिए ताकि दूसरे इलाके के लोगों को भी लाभ हो सके।

इसी प्रकार से रूरल इन्डस्ट्री की स्कीम की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि कोई गरीब आदमी गांव में कोई यूनिट लगाता है तो उसको सरकार की तरफ से मंजूरी

तो दे दी जाती है लेकिन बैंक उनको पैसा नहीं देता है। सरकार की यह स्कीम है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान रूरल एरिया में इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो दस हजार रूपये सरकार देगी, दस हजार रू. वह खुद लगाएगा और 80 हजार रूपया थोड़े ब्याज पर बैंक से मिलेगा लेकिन किसी भी पढ़े लिखे बेरोजगार को इस स्कीम के तहत पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ यह सब गलत बातें इसमें कही गई हैं।

मैं आपका ध्यान एजुके इन डिपार्टमेंट की ओर भी खींचना चाहूंगा। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के और लोक दल के सदस्य रिजर्वे इन के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी वाले रिजर्वे इन चाहते हैं। मेरे पास एक लैटर है जो हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति कल्याण संघ की ओर से दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि 1-10-1980 को एजुके इन डिपार्टमेंट ने दस हजार टीचर्ज लिए हैं लेकिन उनमें हरिजनों को बिल्कुल नहीं लिया गया। वे लोग हरिजनों की बात तो कहते हैं परन्तु दस हजार टीचर्ज में एजुके इन विभाग ने एक भी हरिजन को नौकरी नहीं दी। हरियाणा में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें रिजर्वे इन पूरी हो। यह सरकार खाली नारे लगाती है। चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इन्डस्ट्री है किसी भी डिपार्टमेंट में रिजर्वे इन पूरी नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज से एक साल या डेढ़ साल पहले सरदार लछमन सिंह पीनाना गांव में वाटर सप्लाई स्कीम के

लिए पत्थर रख कर आए थे। पता नहीं आज वह पत्थर कहां चला गया। इसी प्रकार से सी.एम. साहब ने भी कहा था कि सोनीपत में 150 बैडज का हस्पताल बनाया जायेगा। वहां पर जमीन इक्वायर की गई, लाखों रूपया खर्च किया गया लेकिन पता नहीं क्या अड़चन हुई कि वह हस्पताल बना ही नहीं। इस सरकार द्वारा जो पत्थर रखे जाते हैं वे पत्थर ही बन कर रह जाते हैं। यह सरकार खाली दिखावा करती है, प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं करती। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

12.00 बजे

श्री सुरेन्द्र सिंह (तो गाम): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सरकार की तरफ से पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बड़ा अच्छा बजट है। इस बजट में हरिजनों के लिए, किसानों के लिए और आम छोटे व्यापारी के लिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं। मेरे लोक दल के भाइयों और दूसरे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस बजट को किसान विरोधी, हरिजन विरोधी और बैकवर्ड क्लासिज विरोधी बताया है। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के सदस्य इस बात की चर्चा नहीं करते कि जिन किसानों के पास अढ़ाई एकड़ तक जमीन है, उनके खालों की लाइनिंग का खर्चा माफ कर दिया है। इनके राज में क्या था ? जब चौधरी चरण सिंह बदकिस्मती से इस मुल्क के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने जो एक ट्रैक्टर 40 हजार का मिलता था उसकी कीमत 60 हजार कर दी और जो खाद का कट्टा 20 रुपये का

आता था उसकी कीमत 30 रूपये कर दी थी। जब चौधरी चरण सिंह रोहतक में आये तो उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में गरीबी के लिहाज से हमारे मुल्क का नम्बर संसार में 84 था। लेकिन आज हमारा मुल्क गरीबी के लिहाज से संसार में 111वें स्थान पर आ गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मुल्क में गरीबी बढ़ाने में किसी का कन्ट्रीब्यूशन है तो वह सिर्फ पीछे जो हमूतम रही है, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार और उससे पहली वाली सरकार, उनका ही योगदान इस देश को पीछे ले जाने का रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो मेरे भाई बैठे रूलिंग पार्टी के मैम्बर है, वे इस बजट को बड़ा अच्छा बजट बता रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया है। इससे पहले जब पिछले 3 सालों में बजट पेश होते रहे तो क्या इन्होंने उनकी जरा सी भी सही ढंग से नुक्ताचीनी करने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब है कि पिछले 3-4 सालों के जो बजट इस प्रान्त में आये वे जनता पार्टी ने जानबूझ कर इस कदर बनाये कि उनसे आम आदमी, हरिजन और बैंकवर्ड क्लासिज के भाईयों का भला न हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट के बारे में आज चौधरी गया लाल जी, लाल सिंह जी और दूसरी साथी यह कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा खूबसूरत बजट देखने को मिला है। क्या इन्होंने अपने दिल पर हाथ रख करके देखा है कि जब से ये सरकार बेंचो पर बैठे हैं तब से इससे अच्छा बजट न आया हो और इन्होंने

उसकी क्रिटिसाइज किया हो। क्या इन्हें इससे पहले वाले बजटों में कोई कमी नजर नहीं आई ? किसी भी पार्टी के मैम्बर को बजट में अच्छे सुझावों का समर्थन करना चाहिए और जो गलत बातें हो, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस प्रान्त में बिजली की बहुत कमी है। लेकिन इस बजट के अन्दर डिवैल्पमेंट के लिए जो पैसा रखा है, वह 40 प्रति त है और जो नॉन डिवैल्पमेंट एक्सपेंडीचर हैं जिसका डिवैल्पमेंट से कोई खास संबंध नहीं है उसके लिए 60 प्रति त पैसा रखा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज इस प्रान्त में इस कदर खर्चा हो रहा है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। कल इरीगे तन और पावर मिनिस्टर साहब इस सदन में ब्यान कर रहे थे कि अगर हरियाणा बिजली बोर्ड के दफ्तर को हिसार ले जाया जायेगा तो टी.ए.डी.ए. के बहुत खर्चे बढ़ जायेंगे। सदन की सूचना के लिए कुछेक आंकड़े जो मेरे पास हैं, बताना चाहूंगा। हरियाणा बिजली बोर्ड आफिस का किराया एक साल का लगभग 12 लाख रूपये है। यहां पर जो 200 आफिसर्ज बैठते हैं और उनका जो स्टाफ है उनके मकानों का किराया, एक साल का लगभग 38 लाख रूपये है। हिसार के अन्दर लगभग 465 ऐसे मकान हैं जो आज भी खाली पड़े हुए हैं। ये मकान बिजली बोर्ड द्वारा बनाए गए थे। चण्डीगढ़ में जो आफिसर हरियाणा से दौरे पर आते हैं वे बहुत ज्यसादा टी.ए.डी.ए. क्लम करते हैं। चण्डीगढ़ से जो आफिसर हरियाणा में दौरे पर

जाते हैं उनका टी.ए.डी.ए. का खर्चा हरियाणा से चण्डीगढ़ आने वाले आफिसरों के मुकाबिले में कम होता है। चण्डीगढ़ हैडक्वाटर तो सिर्फ अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिले को ही नजदीक पडत्रता है जबकि अन्य जिलों के लिए यह हैडक्वाटर दूर पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर हिसार हैडक्वाटर कर दिया जाये तो बड़ा अच्छा होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, जनवरी, 1980 के अन्दर बहुत से विधायकों ने मिल कर कांग्रेस सरकार की मिनिस्टरी बनाई। इन्होंने अच्छा किया कि कांग्रेस सरकार की मिनिस्टरी बनाई। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी यह जिम्मेदारी है कि श्रीमति इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के मुताबिक कार्य करें। उनकी नीति के अनुसार हमें गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने चाहिए। इन भाइयों की हमदर्दी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां पर एक सर्वोडीनेट सर्विसिज सिलेक्शन बोर्ड है। इस बोर्ड के द्वारा दो तीन साल पहले कुछ कैटेग्रीज की पोस्टों के लिए एग्जाम हुए थे। जब चौधरी रिजक राम जी बोल रहे थे तो इन्होंने कहा था कि जिन भाइयों ने नौकरी के लिए आवेदन पत्र भी नहीं दिया था, उनको भी नौकरी में ले लिया गया, यानी उनको नौकरी मिल गई। इस सरकार ने करीब 3 हजार एडहौक एम्पलाइज को, जोकि अपने

प्रान्त की सच्चे दिल से सेवा कर रहे थे, सर्विस से हटा दिउया है। उनको इस तरह से हटाया गया है जैसे उनका इस प्रदे 1 से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारी सरकार ने करीब 2627 नए आदमियों को लगा लिया, जिनका कोई योगदान नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह से काम नहीं चलता। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जिन आदमियों को निकाला गया है, उनको दोबारा भर्ती कर लिया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस सदन में चौधरी रिजक राम जी और एक विरोधी पक्ष के मैम्बर कह रहे थे कि हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड में काफी घपला है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब इस बोर्ड के बारे में बात हो रही थी तो आपने भी एतराज उठाया कि जो आदमी इस सदन में अपने आप को डिफेंड न कर सके, उसके खिलाफ इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आपको भी यह सोचना चाहिए था कि जब कोई हरियाणा के इन्ट्रैस्ट की बात कर रहा हो तो उस बात को पूरा कर लेने देना चाहिए। हरियाणा के हित की बात हम सभी ने मिल जुल कर करनी है।

चौधरी गया लाल:

श्री सुरेन्द्र सिंह:

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

श्री सुरेन्द्र सिंह:

श्री उपाध्यक्ष: सुरेन्द्र सिंह जो आप बैठिये। अब श्री इन्द्रजीत सिंह जी बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तो चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। वे हाउस के लीडर हैं। सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, वे भी मैंने बताये हैं।
(गोर)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गये हैं। अब श्री इन्द्र जीत सिंह बोलेंगे।

Sh. Surender Singh: Sir, I have yet to open the accounts. (Interruptions.)

Mr. Deputy Speaker: Surender Singh Ji, your time is over. Please take your seat. I have already called upon another Member to speak.

डा. मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।
(व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Doctor Sahib, this is no point of order.

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय,

चौधरी गंगा राम:

चौधरी भजन लाल:

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना): डिप्टी स्पीकर साहब, 16 मार्च को जो बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हाउस में पेश किया है, मैं उसका समर्थन केवल इसलिए करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं रूलिंग पार्टी का एक सदस्य हूँ। बल्कि मैं यह खुद महसूस करता हूँ कि यह जो बजट पेश किया गया है, यह काबिले तारीफ है। डिप्टी साहब, आप जानते हैं कि पिछले कुछ अर्से से कुदरत ने इस प्रान्त के किसानों के साथ कुछ इस तरह का खेल खेला है कि उनकी माली हालत सुधरने की बजाए और खराब हो गयी। बावजूद इस बात के कि सरकार ने भी काफी प्रयत्न किए हैं। उनकी हालत गिरती ही जा रही है। अगर इस बजट में किसानों के ऊपर कोई टैक्स लग जाता तो मैं समझता हूँ कि जिन फाइनेंसियल डिफिकल्टीज के सरकमस्टांसिज के अन्दर वे आजकल फंसे हुए हैं, उनको और भी दिक्कत होती। इसी बात की सोच कर मुझे एक बहुत ही बड़े आदमी औलिवर गोल्डस्मिथ के लफज याद आते हैं:—

For Princes and Lords

may flourish or may fade,

a breath can make them as a breath has made;

But a bold peasantry a country's pride;

Once destroyed can never be supplied.

मतलब यह है कि इस वक्त जो किसान की मौजूदा हालत है, उसको देखते हुए जिस तरह का बिना टैक्स का यह बजट पे 1 किया गया है, यह सराहनीय है। यह किसान के हित को देखते हुए बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यहां इस सदन के अन्दर बैड़ कर अपने टी.ए.डी.ए. बढ़ाने के लिए हम जो मर्जी आये कर लेते हैं, या पे-कमी इन की रिपोर्ट आती है, तो हम मुलाजिमों के पे-स्केल्ज बढ़ा देते हैं लेकिन किसान ही ऐसा आदमी है जिसको न कोई टी.ए. मिलता है और न ही कोई डी.ए. मिलता है। जो कुछ भी उसको मिलता है वह उसकी मेहनत का फल मिलता है। हमारी सरकार इस बजट में टैक्स नहीं लगा रही है, तो मैं यह समझता हूं कि यह हरियाणा के हित के लिए अच्छी बात की गयी है। इसके अलावा जो प्रावधान किसानों की बहबूदी के लिए, बिजली और पानी मुहैया करवाने के लिए किया गया है, उसकी भी मैं दाद देता हूं। सिक्सथ फाईव ईयर प्लान के तहत 1981-82 में इरीगे इन और एग्रीकल्चर के लिए 157 करोड़ रूपया रखा गया है। यह बड़ी सही बात की गयी है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इससे हमारे प्रदे 1 के अन्दर बिजली व पानी की कमी पूरी होगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरफ जो महत्व दिया गया है, वह काबिले तारीफ है। इसी तरह से एक बोल्ड कदम सरकार ने और उठाया है। जिस किसान के पास अढ़ाई एकड़ तक जमीन है उसका खालों की लाइनिंग का खर्चा माफ कर दिया गया है और जिसके पास अढ़ाई एकड़ से ज्यादा जमीन है, उससे सिर्फ 50 प्रति 100 खर्चा लेंगे। इसके अलावा

सरकार का यह ब्यान भी आया है कि एम.आई.टी.सी. को जितना भार्त्फल लाइनिंग करने की वजह से होगा, उसे सरकार अपने खर्च से मभ्अ करेगी। यह एक बहुत ही अच्दी बात की गयी है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्या पता कितना भार्त्फल आ जाये। मैं इस बात के लिए सरकार को खासकर खुर गीद भाई को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। भूगर केन की प्राईस बढ़ा कर भी 26 रूपये प्रति क्विंटल कर दी है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। पुलिस के खर्च के अन्दर काफी इजाफा किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, पुलिस के बारे में मैं। केवल इतना ही कहना चाहता हूं Our police system suffers from inherent weakness, which has been left over from the Birthish times. But whatever may be said about it, I think, it is still one of the best police force in the country. जो यह साढ़े चार करोड़ रूपये के करीब पुलिस की हाउसिंग ओर दूसरी फ़ैसिलिटीज के लिए रखा गया है, इससे उनका मोरल बढ़ेगा। अगर हम पुलिस वालों का सिर्फ़ क्रिटीसिजम ही करते जायें और सोचें कि इससे उनका रवैया ठीक हो जायेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी राय में उनको ठीक करने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि हम उनको ट्रेनिंग दें और दूसरा यह कि हम उनके अन्दर फेथ रखें तथा उनकी जितनी हम हैल्प कर सकते हैं, करें। इस बजट के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह तो सैल्फ एवीडैन्ट है। कुछ सुझाव इस बारे में अब य देना चाहूंगा। सबसे पहले तो अनएम्पलायमेंट के बारे में मैं कुछ

कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अन्दर काफी अनएम्प्लायमेंट बढ़ गयी है। किसान लोग जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, वे यह चाहते हैं कि उनका भी एक आध लड़का नौकरी में आ जाये इसके लिए बेतक उसके ऊपर 2 प्रतिशत या 4 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाये। जब उसको यह पता लग जाये कि उसका एक लड़का नौकरी लग जायेगा तो वह खुशी से आपको थोड़ा बहुत टैक्स देने के लिए तैयार हो जायेगा इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान के लड़कों को भी एम्प्लायमेंट देने की तरफ तवज्जह देनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैडीकैप्ड के बारे में कहना चाहता हूँ। गांव के अन्दर बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं, अपना सामान नहीं उठा सकते हैं। ऐसी हालत में उनके घर वाले किक मारकर उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और वे बेचारे दर-दर की ठोकर खाते रहते हैं और भटकते रहते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार खासतौर पर कुछ करे और जो लड़के मेहनत करके पढ़ लिख गए हैं उनको सब से पहले सर्विस के अन्दर लेना चाहिए।

अब मैं रीजनल इम्बैलेंसिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे महेन्द्रगढ़ और भिवानी जो पहले से ही बैकवर्ड चले आए हैं। सर्वे आफ इंडिया की टीम ने महेन्द्रगढ़ जिले का

सर्वे किया था। उनसे यह जानकारी मिली है कि महेन्द्रगढ़ में लाइम स्टोन की खाने है। डिप्टी स्पीकर साहब, दादरी के अन्दर एक सीमेन्ट फ़ैक्टरी हैं लेकिन उसमें झगड़ा होने के कारण वह काफी दिनों से बन्द पड़ी है। महेन्द्रगढ़ में लाइम स्टोन की खाने होने को मददेनजर रखते हुए वहां पर कोई सीमेन्ट की फ़ैक्टरी खोली जाए जिससे कि सीमेन्ट की किल्लत भी दूर हो जाएगी और दूसरी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। अगर किसान केवल ऐग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है तो वह फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए किसान के लिए कोई ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे कि उसकी माली हालत सुधरे। हमारे यहां के लोगों को जानवरों से बड़ा प्यार है। इसलिए कम से कम ऐनीमल हस्बैन्डरी विभाग, अमुल कौम्पलैक्स जो गुजरात में हैं, उस पैटर्न पर हमारे यहां एक कौम्पलैक्स बनाने में काफी मदद कर सकता है। उससे लोग गाय भैंस रखकर दूध की प्रोडक्शन कर सकेंगे और अपनी माली हालत को सुधार सकेंगे। (घंटी) बस मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं और वह है जौब्ज के बारे में। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ विभागों में जौब्ज ज्यादा निकलते हैं और कुछ विभागों में कम जौब्ज निकलते हैं। देखा यह गया है कि एक मंत्री जिसके पास ऐसा विभाग है जिसमें ज्यादा जौब्ज निकलते हैं तो वह उस विभाग में अपनी ही कांस्टीच्यूएंसि के लोगों को लगा लेता है। उस मंत्री की यही कोशिश होती है कि उस महकमें में अपने हल्के के लोगों को लगा लें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर महकमें के अन्दर हर डिस्ट्रिक्ट

का बराबर का भोयर होना चाहिए न कि हरेक मंत्री अपने विभाग में अपने ही हल्के के आदमियों को लगा लें। बस मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत भुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, वित्त मंत्री ने जो बजट पे 1 किया है

नेमिंग आफ मैम्बर

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, रूलिंग पार्टी के तीन आदमी लगातार बोलने लग रहे हैं। आप हमें भी टाईम दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप डिमान्डज पर बोल सकते हैं। Now the hon. Member Mr. Lehri Singh, has already started speaking. (Interruptions) Please take your seat.

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, जब से हाउस भुरु हुआ है तब से मैं किसी चीज पर नहीं बोला हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी की तरफ से मुझे जो लिस्ट दी गई है, उसमें आपका नाम ही नहीं है (गोर एवं व्यवधान) ।

am calling upon the members according to the names given to me by the parties concerned.

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, नम्बर तो बोलने का हमार है। अगर इनका नाम नहीं है, तो किसी और मैम्बर को हमारी तरफ से बोलने दिया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्ट्रैंथ के हिसाब से रूलिंग पार्टी के सदस्यों को अब भी बहुत कम समय दिया गया है। जितना समय दिया गया है वह मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे टोटल पांच आदमी बोल पाए हैं। हमें जितना टाइम बजट पर बोलने के लिए मिलना है, कृपा वह हमें बता दें। (गोर एवं व्यवधान) हमारे साथे तो ज्यादाती हो रही है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी आप बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान) This is no point of order.

चौधरी गंगा राम: मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आप नहीं चाहते कि

श्री उपाध्यक्ष: ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी गंगा राम:

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी गंगा राम वर्मा):
डिप्टी स्पीकर साहब, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं।

चौधरी गंगा राम:

Mr. Deputy Speaker: I name Ch. Ganga Ram. Please leave the House. (Interruptions) Ganga Ram Ji, I have named you. Please leave the House.

(The Hon. Member Ch. Ganga Ram did not withdraw from the House and continued speaking)

Mr. Deputy Speaker: Remove him.

(At this stage the Serjeant-At-Arms went to the hon. Member, Ch. Ganga Ram who then withdrew from the House.)

वाक आउट

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। (गोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, हमें सरकार की पोल खोलनी है, इसलिए मेरी सबमीशन है कि हमें समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आपाको पूरा समय दिया जा रहा है।
(गोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: रूलिंग पार्टी के लगातार तीन आदमी बोले हैं। अब आप हमें टाईम दीजिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो लिस्ट आपकी तरफ से आई हैं, उसमें चौधरी गंगा राम का नाम नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अब तक रूलिंग पार्टी के तीन मैम्बर लगातार बोल चुके हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जिस हिसाब से समय बांटा गया था उसमें से लोकदल को कल भाम तक साढ़े तीन परसैन्ट ज्यादा समय दिया गया है और रूलिंग पार्टी को समय कम दिया गया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, रूलिंग पार्टी के 52 सदस्य हैं, लोकदल के बाइस सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्यारह मैम्बर है और जनता पार्टी के चार मैम्बर है। इस हिसाब से आप टाईम बता दीजिए कि कितना कितना मिलना है। जितना टाईम हमें मिला है वह कम से कम पच्चीस परसैन्ट कम मिला है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ डिस्क्रीमिनेशन हो रही है, इसलिये हम वाक आउट करते हैं।

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री लहरी सिंह मेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट से एक आम आदमी को भी बहुत फायदा हुआ है। इसको पढ़कर यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा बढ़िया बजट है कि भायद ही इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा बजट पे । किया हो। इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे प्रदे । के प ़ुपालन मंत्री, चौधरी िावराम वर्मा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र में काफी उन्नति की है। जिस दिन से इन्होंने इस विभाग को सम्भाला है, इन्होंने इस विभाग के कार्य को आदर तेजी से आगे बढ़ाया है चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय मवे ि ायों की प्रान्त में केवल 20 डिस्पैन्सरियां थीं और अब इन्होंने इसकी जरूरत को देखते हुए डिस्पैन्सरियों को बढ़ाया है। मंत्री जी गांव के रहने वाले हैं इसलिए डंगरों को हर दिक्कत को वे अच्छी तरह से जानते हैं। इस बड़े काम के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मैं चौधरी भजन लाल जी की सरकार की इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि वह हमारी पार्टी की सरकार है बल्कि इसलिए करता हूं कि जो कार्य इनकी सरकार ने किये हैं और कर रही है, उन से एक आम आदमी को भी काफी राहत मिली है। इन्होंने हर आम आदमी की तकलीफ को सम्झा है। जिन गरीबों के पास खाने को रोटी नहीं

है पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है उन लोगों के लिए हमारी सरकार ने वास्तव में ही बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। इसके साथ साथ मैं अपनी सरकार से एक अपील करूंगा कि चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी गांव हो चाहे मेरा गांव हो या किसी और का गांव हो हर तीन मील के बाद डंगरों की बेहबूदी के लिए एक डिसपन्सरी होनी चाहिए और साथ साथ एक मिडल स्कूल भी होना चाहिए। जो दो करोड़ रुपये की राशि हमारी सरकार ने पंचायतों के लिए रखी है, उसको बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पंचायतों के हस्पताल खोले जाने चाहिए ताकि गरीब हरिजनों और गरीब लोगों के पंचायतों को भी राहत मिल सके।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी सरकार को इस बात की भी मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि सदियों से पिछड़ा हुआ जो मेवात का इलाका था, उस तरफ किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया था लेकिन हमारी सरकार ने इस काम के लिए पिछली बार सवा करोड़ रुपया रखा था जोकि अब खत्म होने जा रहा है। अब इस साल इस काम के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। यह सरकार का बड़ा ही सराहनीय काम है। उन लोगों के हालात को सुधारने के लिए, उनकी बेहबूदी के लिए यह रुपया रख कर एक अच्छा स्टेप सरकार ने उठाया है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, अभी यहां पर हमारे विरोधी दल के भाई बावेला मचा रहे थे कि इस सरकार ने हरिजनों के लिए और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं चौधरी भजन लाल जी की सरकार को और कांग्रेस (आई) की सरकार को बधाई देता हूँ जिसने बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए, हरिजनों के लिए और भाई गंगा राम जैसे विकलांग वर्ग के लिए भी बड़ा कुछ किया है। यह पहली सरकार है जिसने विकलांगों के लिए भी रिजर्वेशन की है। मैं डिटेल्स के साथ बताना चाहता हूँ कि इस सरकार से पहले हरिजनों को जो सविधाएं दी जाती थीं, उनके लिए बहुत कम राशि का प्रावधान था लेकिन अब इस सरकार ने इस काम के लिए वर्ष 1981-82 में 35.57 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है जोकि इस वर्ष के योजना बजट का साढ़े 12 परसेंट है यह पैसा हरिजनों की भलाई के लिए, उनकी डिवैल्पमेंट के लिए और उनकी हालत को सुधारने के लिए रखा गया है। इसके अलावा हरिजन लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोग्राम के तहत सेंटर की सरकार से हमें दो करोड़ रुपये की सहायता मिली है और 1.80 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने खुद किया है यानी कुल मिलाकर 3.80 करोड़ रुपये इस प्रोग्राम के लिए रखा गया है। फिर भी विरोधी पक्ष के भाई कहते हैं कि यह सरकार हरिजनों के लिए कुछ नहीं कर रही है।

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं इस विभाग के जो मुखिया हैं, उनको और सम्बन्धित मंत्री महोदया बहिन भाकुन्तला

जी को भी बधाई देता हूँ। जिस दिन से इन्होंने इस विभाग को सम्भाला है, तब से जगह जगह जाकर के चाहे कोई भी हलका हो, हरिजनों को अपने हाथ से लोन का वितरण किया है। इसलिए इस बजट को एक आम आदमी का बजट कहा जाना ही उपयुक्त होगा क्योंकि आज सरकार आम आदमी के ऊपर ही काफी खर्चा कर रही है और गरीब आदमी को इससे राहत का एहसास हो रहा है। स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हुआ और इस बजट का जोरदार भावों में समर्थन करता हुआ केवल एक दो प्वायंट ही और कह कर समाप्त करूंगा (तोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, इनको बोलते हुए काफी टाईम हो गया है। (तोर)

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, मैं केवल एक दो मिनट ही और लूंगा। मैं अपनी सरकार को एक दो सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा हलका रादौर है। उस इलाके के एहसान सारे हरियाणा के ऊपर हैं। वहां से वैस्टर्न यमुना कैनल गुजरती है और साथ ही मेरे हल्के में से होकर आगमैन्टे इन कैनल भी गुजरती है जिससे की महेन्द्रगढ और भिवानी के इलाकों के किसानों को फायदा पहुंचता है। ये नहरें मेरे इलाके के किसानों की धरती की छाती को चीर कर गुजरती है। इन नहरों से दूसरे इलाकों को तो फायदा पहुंचता है लेकिन मेरे हल्के के लोगों को इन नहरों का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। मेरे इलाके के दूसरे इलाकों के ऊपर बड़े भारी एहसान हैं, जिनको कभी भुलाया नहीं

जा सकता। इसलिए मेरी अपनी सरकार से प्रार्थना है कि चूंकि उस पानी का मेरे इलाके को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इस इलाके की बहबूदी के लिए भी सरकार पूरा पूरा ध्यान दें।

श्री भागी राम (एलनाबाद अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इस समय वर्ष 1981-82 के बजट पर आम चर्चा चल रही है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। पिछले 30 सालों से आज तक कागजों में और किताबों में जो कुछ हरिजनों को मिलता रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। बजट के एक एक पन्ने के ऊपर हरिजनों और बैंकवर्ड लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो गरजता है, वह बरसता नहीं। ये सब इनकी कहने की बातें हैं वास्तव में हरिजनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और उन्हें एक्सप्लायट किया जा रहा है। सरकार ने एलान किया कि हम हरिजनों के मुहल्लों में लाइट दे रहे हैं। ऐसा कहकर यह सरकार हमारे साथ धोखा और खिलवाड़ कर रही है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि एक मुहल्ले में पोल गाड़ दिया और एक होल्डर लगाकर बल्ब लगा दिया और कहते हैं कि कनैक्टान दे दिया। लाईट वगैरह का कहीं कोई प्रबन्ध नहीं। यह काम इस सरकार का है, जो यह हरिजनों की बहबूदी के लिए कर रही है। उसके बदले में सारे गांव वालों के मीटरों पर एक एक रूपया बढ़ा

दिया ताकि गांव वालों का झगड़ा उन सब हरिजनों के साथ हो जाये। अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि हम हरिजनों के घरों में भी लाइट का प्रबन्ध कर रहे हैं। यानी उनके घरों में बिजली फिट करवा रहे हैं। यह ऐसी फिटिंग करवा रहे हैं कि खाली एक होल्डर लगाकर उसमें एक बल्ब लगा देते हैं और उसके 50 रूपए चार्ज करते हैं। (भोम भोम की आवाजें) जो फिटिंग सरकार करा रही है उसमें 15 रूपये का भी सामान नहीं होता लेकिन सरकार हरिजनों से 50 रूपए लेती है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि जो बल्ब लगाया जाता है वह भी फ्यूज बल्ब लगाया जाता है। ऐसा करके ये हरिजनों को गुमराह करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज भोर सिंह जी ने एक सवाल का जवाब दिया कि झज्जर क्षेत्र में 195 कनाल और 5 मरले जमीन सरप्लस थी जोकि कुछ आदमियों में 8-8 कनाल के लगभग बांट दी गई है। तो अब आप देखें कि उस कांस्टीच्यूएन्सी में जो सरप्लस जमीन थी वह सारी बांट दी लेकिन जो हरिजन बच गये हैं, उनका क्या इलाज करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, ये झूठे नारे लगा रहे हैं। (विघ्न) आपको पता है कि आठ कनाल जमीन पर का त तो हा नहीं सकती इसलिए इन्होंने उनको बसने के लिए वह जमीन दी होगी। (गोर) हमारे हाथों में अगर ताकत होगी तो हम अपना हक लेकर दिखाएंगे। (गोर) (घंटी) सिरसा में अध्यक्ष महोदय, सरकार हरिजन मुजारों पर सरप्लस जमीन जानी चाहिए उन लोगों की जमीन सरपंच नहीं निकाल रहे। यह हरिजनों से धोखा है।

श्री अध्यक्ष: और कुछ रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आप कृपया बैठें।

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): स्पीकर साह,ब अभी तक इस हाउस के आनरेबल मैम्बरान में से 26 आनरेबल मैम्बर्ज ने बजट के ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसकी भुरुआत हमारे बुजुर्ग बाबू मूल चन्द जैन जी ने की थी लेकिन इस वक्त वे हाउस में हाजिर नहीं है। जो बाते उन्होंने कहीं, उनके बारे में सब से पहले मैं उन्हीं के लिए रैफर करूंगा। सब से पहली बात उन्होंने यह कही थी कि इस बजट में से 20 करोड़ रूपये का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वह कैसे गुम हो गया ? उन्होंने नान प्लान और प्लान एकसैंडिचर दोनों को जमा कर लिया और जमा करने के बाद कह दिया कि इनका जोड़ 620 करोड़ रूपया बनता है। फिर कहा कि जो बजट स्पीच के पेज 27 पर आंकड़े दिये हैं उसके मुताबिक टोटल खर्चा 600 करोड़ रूपय बनता है इसलिए 20 करोड़ का इसमें फर्क है। जनाब वे तो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एक बार ही नहीं बल्कि दो दो बार फाइनेंस मिनिस्टरी का इन्तजाम कर चुके हैं। वे अगर थोड़ा सा गौर से देखते तो उनको सारी बातों का अन्दाजा हो जाता कि टोटल प्लान बजट एस्टीमेट्स के जो हम कागजात सामने रखते है वे सिर्फ वहीं नहीं होती जिन पर असैम्बली वोट करती है बल्कि बहुत सी आटौनामस बाडीज ऐसी होती है जिनका अपने खर्च से भी कुछ प्लान में हिस्सा डाला जाता है। यह बात ऐसी नहीं कि छिपी

हुई हो। मैंने अपनी स्पीच के दौरान पेज चार पर यह बात कही थी:—

“In terms of plan activities we commenced the year 1980-81 with an approved plan outlay of Rs. 240-50 crores.....”

खर्चा बढ़ता गया और प्लान के अन्दर हमने भाार्ट फाल नहीं आने दिया। पहले प्लान को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारी अचीवमेंट 253.78 करोड़ रूपये की थी। एक दूसरे हमारी साथी चौधरी राम लाल वधवा जी ने यह समझ लिया कि यह 1981-82 का प्लान है। हमारा 1981-82 का जो प्लान है वह 290 करोड़ रूपए का है और इसके जो भी आंकड़े आपके सामने आए हैं, उनसे मैं यह बता दूंगा कि 290 करोड़ रूपए का प्लान हमने कहां कहां से पूरा किया है। वे किताब को भी अगर देखते तो जो फाइनेंस सैक्रेटरी की तरफ से मैमोरैंडम पे 1 किया जाता है, उसमें सारा विवरण दिया होता है। यह मैमोरैंडम पेज 19 पर दिया हुआ है। पेज 19 पर अगर बाबू जी देखते तो उस पर हमने यह दिया हुआ है कि 290 करोड़ रूपये को किस तरह से पूरा करेंगे। उसमें जो हमारा 1981-82 का टोटल बजट एस्टीमेट्स दिया हुआ है वह रैवेन्यू साइड पर 103.64 करोड़ रूपये का है और कैपिटल साइड पर 119.33 करोड़ रूपये का है और जो हमें लोन मिलेगा वह 62.07 करोड़ रूपये हैं यह टोटल मिला कर 285.04 करोड़ रूपये हो जाता है। इसमें से अगर सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीमों को निकाला जाए तो करीब 30.10 करोड़ रूपये की हैं, तो

हमारा 254.94 करोड़ रूपए रह जाता है। फिर हमने जो आटोनोमस बाडीज से कंट्रीब्यू 1 न डाली जाएगी, उसकी डिटेल् दी है। उसमें हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से 30.66 करोड़ रूपए एल.आई.सी. से अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 83 लाख रू. मिलेगा। मोटर ट्रांसपोर्ट डैपरीसएि 1 न रिजर्व फंड से जो हमारे पास आएगा वह 1.82 करोड़ और 1.75 करोड़ रू. रिसीट्स एन्ड रिकवरीज आन कैपिटल अकाउंट्स आफ कोआप्रे 1 न का आएगा। इस तरह से हमारा एक साल का टोटल प्लान 290 करोड़ रूपए का बनता है। अब बाबू जी नहीं हैं। वे कह रहे थे कि वे सारे पंजाब में फर्स्ट आए थे वे अगर पंजाब में फर्स्ट आए थे तो उनका मैथेमैटिक्स तेज होगा। लेकिन जो आदमी बहुत तेज होता है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि उसे 55 साल की उमर में रिटायर कर दे वरना उसे बाद वह कन्फ्यूज हो जाता है। (हंसी) अब बाबू जी ने खुद ही बताया था कि वे 66 साल के हो चुके हैं इसलिये इनको तो माफ करते हैं। (हंसी) स्पीकर साहब, चौधरी सतबीर सिंह के लिए मैं क्या कहूँ ? इन्होंने बजट भी देखा है और पढ़ा भी है। लेकिन इन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि यह बजट तो बड़ा कंफ्यूज्ड बजट है। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त ये खुद फाईनेंस मिनिस्टर थे तब इन्होंने बजट पे 1 किया, उस समय भी ये कंफ्यूज्ड थे। मेरे साथी कभी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलते हैं और निकलें भी कैसे ? किसी बात का अध्ययन करें तो निकलें। इन्होंने बजट स्पीच को उठा कर नहीं देखा, किसी डाकुमेंट को नहीं देखा और कहने लगे कि इसमें तो कोई भी

स्कीम नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि इसमें डेरी डिवैल्पमेंट के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, मिनी डेरीज की स्कीम भी छोड़ दी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको क्या बताऊं कि बजट स्पीक के कौन कौन से पेज पर कौन-कौन सी स्कीम्ज दी हुई हैं। इन्होंने मिनी डेरीज के बारे में जो फरमाया है कि कोई जिक्र नहीं है तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि प्लान स्कीम्ज का जो डाकुमेंट है आप उसके पेज 84 पर देखें। उसमें यह लिखा हुआ है कि वर्ष 1981-82 के लिए हमने 43 लाख रूपया गवर्नमेंट फण्ड से रखा है और इसके अलावा नै नल इंस्टीच्यू ांज तथा बैंक्स को मोटीवेट किया है। ये गवर्नमेंट के बराबर का पैसा देकर हमारी स्टेट में मिनी डेरीज खुलवाएंगे। (गोर)

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मंत्री जी और ही जवाब दे रहे हैं, दसअसल मेरे कहने का मकसद यह था कि (गोर)

श्री अध्यक्ष: आपने जो कहा है वह भी रिकार्ड में है और जो मंत्री जी कह रहे हैं वह भी रिकार्ड में है। इसमें प्वायंट आफ आर्डर की कोई बात नहीं है। कृप्या आप बैठ जाईए।

चौधरी खुर िद अहमद: अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी जितने बजट के बारे में कंफ्यूज्ड थे उससे ज्यादा इन स्कीम्ज के बारे में कंफ्यूज हो गए जो कि बजट डाकुमेंट्स में दी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 1980-81 में इसके लिए 34 लाख 15

हजार रूपया दिया था और इस साल 1981-82 के लिए 43 लाख रूपया प्रोवाइड यिका है। यदि मेरे साथी डाकुमेंट्स को उठा कर देखते तो सारी चीजें इनके सामने आ जाती। हमने यही नहीं कियसा बल्कि पहले हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो स्कीम थी उसमें एक नुक्स रह गया था उस नुक्स को सुलझा कर हमने ग्रुप गारंटी स्कीम के तहत कवर कर लिया है। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं है अब वे भी इस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट पैसा देगी वह सबसिडी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा या उसे इंट्रैस्ट को माफ कर दिया जाएगा। इस ग्रुप गारंटी स्कीम के तहत जो गरीब, मजदूर या किसन हैं, वे कर्जा ले सकते हैं और एक दूसरे की आपस में जमानत दे सकते हैं जैसे तीन आदमियों ने लोन लेना है तो वह आपस में एक दूसरे की गारंटी दे सकते हैं और इस प्रकार से बगैर जमीन जायदाद वाले को भी कर्जा मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी से कहूंगा कि वर्ष 1981-82 में दो हजार यनई मिनी डेरीज खोली जाएंगी ओर 9200 प ु लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मास्टर हुकम सिंह जी ने बजट पर चर्चा करते हुए डेरी डिवल्पमेंट स्कीम के बारे में कहा कि पहले दूधारू प ुओं के लिए ईनाम दिया जाता था, इस बजट में उस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने फाजिल दोस्त मास्टर हुकम सिंह को बताना चाहूंगा कि यह स्कीम हमारी सरकार ने 4 मार्च 1980 को भुरु की थी और इस स्कीम के तहत जो दूधार प ु हैं, जो ए वन कैटेगरी में आते हैं,

उनको एक साल में 1500 रूपए ईनाम के लिए दिये जाते हैं। यह स्कीम सिर्फ एक ही साल के लिए नहीं है बल्कि दो तीन साल तक चलती रहेगी और एक ही पशु को तीन साल तक यह ईनाम मिलता रहेगा। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि अच्छी नस्ल वाले पशुओं को तीन ब्यांत तक देखा जाएं और उसकी प्रोजनी से तीन बच्चे हो जो हमारी स्टेट के काम आए। इसी प्रकार से, इस स्कीम के तहत एक लाख 92 हजार रूपया 31 मार्च, 1981 तक दिया जाएगा और 1981-82 में इस स्कीम के तहत दो लख रूपये का प्रोवीजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाई ने बजट को देख ही नहीं। अब मैं डेरी डिवैल्पमेंट स्कीम के साथ साथ एनीमल हसबैंडरी के बारे में बताना चाहूंगा। एनीमल हसबैंडरी का जिक्र मैंने सारे डाकुमेंटस में किया है जिसमें यह लिखा है कि आने वाले साल में कितने स्टॉकमैन सैंटर्ज खोले जाएंगे, कितने पशुओं के लिए डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी और कितने पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि एक मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में यह बताया था कि दूधारू पशुओं के लिए जो 1500 रूपए ईनाम देने वाली स्कीम थी, वह बंद कर दी गई है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इस प्रकार से हाउस को मिसलीड किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो मिनिस्टर साहब

यह कह रहे हैं कि यह स्कीम अभी चालू है और दूसरी तरफ दूसरे मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि यह स्कीम बंद कर दी गई है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकार्ड चेक कर लें और मामला प्रिविलेज कमेटी को दे दीजिए।

Mr. Speaker: All right. I will check up the documents and refer it to the Government for their comments.

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी विठ्ठल राम वर्मा):
स्पीकर साहब, यह स्कीम पहले नहीं थी। इस सरकार ने बनाई है और अब चल रही है। यह इन्होंने गलत कहा है कि स्कीम बंद है।

चौधरी खुरशद अहमद: स्पीकर साहब, दूसरे मेरे साथ चौधरी रिजक राम और बाबू मूल चन्द जैन जी ने कहा है कि नान प्लान का खर्चा ज्यादा हुआ है। दोनों तरफ के कुछ साथियों ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां भी चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं वहां पर लोगों की बहुत सारी मांगों को मान लेते हैं और उनका एलान भी कर देते हैं। इस बात को देखते हुए नान प्लान का खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक सैट अप में लोगों की सभी मांगे मानी जानी चाहिए। मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, हम उनको पूरा करेंगे। लोग यह उम्मीद रखते हैं कि डिप्लॉयमेंट के काम उनके गांवों में, उनके इलाकों में होने चाहिए इसलिए उन कामों की मांगे लीगे हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने पेश करते हैं। अगर

चीफ मिनिस्टर साहब उन मांगों को मानते हैं तो हम उन वायदों को पूरा भी करते हैं क्योंकि हम हरियाणा की जनता के सही नुमायंदे हैं। यदि उनके वायदों को पूरा करने से नान प्लान में खर्चा बढ़ जाता है तो कोई गलत बात नहीं है।

श्री रघुनाथ गोयल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि 3 दिसम्बर, 1979 को चीफ मिनिस्टर साहब ने कैथल में 10 हजार जनता के सामने यह वायदा किया था कि कैथल को फुल फ्लैज्ड डिस्ट्रिक्ट बना देंगे लेकिन अभी तक उस वायद पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

13.00 बजे

चौधरी खुर गिद अहमद: स्पीकर साहब, हमारे एक साथी चौधरी रिजक राम ने अपनी स्पीच में कहा कि इरीगे गन और पावर के मामले में सोनीजत डिस्ट्रिक्ट की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जा रही। सी.एम. साहब ने कुछ वायदे किये थे, वे पूरे नहीं किये गये। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 37 माइनर स्कीमें और कुछ एक्सटैन् गन वर्क स्टार्ट किये गये हैं जिनमें से 12 पर इस वक्त काम चालू है। कुछ जगहों पर अलाइनमेंट के झगड़े पड़े हुए हैं। टोटल 37 स्कीमें हैं और जहां जहां सी.एम. साहब ने अनाउंस किया है, वहां पर पूरे तौर पर काम चल रहा है और

किसी इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। सारे इलाकों को यकसां तौर पर ट्रीट किया जा रहा है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा था कि 15 साल लग जायेंगे इन स्कीमों को कम्पलीट होने में। (व्यवधान)

चौधरी खुर गिद अहमद: जितना भी टार्मि लगे, हम पूरा करेंगे। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा था कि नान प्लान एक्सपैंडीचर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। कुछ आइटम्ज ऐसी हैं जिन पर हाउस में काफी चर्चा हुई। नान प्लान एक्सपैंडीचर के तहत 11.47 लाख रुपया एजुके ान में कुछ नई स्कीमों के चालू होने से बढ़ा है। प्राईवेट इन्स्टीच्यू ान्ज को टेक ओवर किया गया और स्कूलों और कालेजों को 95 प्रति ात ग्रांट दी गई।

श्री मनी राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक मनोहर लाल मैमोरियल कालेज है, वहां आज भी हड़ताल है

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं ळे, आप बैठ जाइए। अगर कोई जायज प्वायंट आफ आर्डर हो तो आप जरूर रेज करें, लेकिन अन नसैसरी प्वायंट आफ आर्डर रेज न करें।

चौधरी खुर गिद अहमद: अगर किसी कालेज के बारे में कोई प्वायंट आनरेबल मैम्बर के पास है तो सैंकिंड सिटिंग में डिमांड्ज पर डिस्क ान होगी। उसमें एजुके ान की एक डिमांड

है, उस वक्त आनरेबल मैम्बर जो कुछ कहना चाहें, कह लें। स्पीकर साहब, डा. मंगल सैन ने हाउस में जो कुछ कहा, उस पर मैं मोटे मोटे आंकड़े हाउस में रख कर बताना चाहता हूँ। कुछ नैचुरल कलैमिटीज की वजह से हमें खर्च बढ़ाना पड़ा क्योंकि कई चीजों पर खर्च करना बहुत जरूरी था। आनरेबल मैम्बर इस बात को मानेंगे कि अगर किसान पर कोई मुसीबत आती है तो उसको राहत देने के लिए पैस की मदद देनी चाहिए। आप देखें, कल भी ओले पड़े। अगर इस किस्म की नैचुरल कलैमिटीज हो जाती है तो किसान को राहत से कैसे महरूम किया जा सकता है ? जो कुछ खर्च यिका वह सरकार ने किसान के हित में यिका है। जब जब उनको पैस की जरूरत पड़ी, जितना हो सका किसान को पैसे दिये गए औ नैचुरल कलैमिटीज की वजह से जहां जहां नुकसान हुआ उसको पूरा यिका। कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर जितनी लायबिलिटीज है, उनको पूरी तरह डिसचार्ज यिका गया। नैचुरल कलैमिटीज की वजह से खर्च में जो वृद्धि हुई, उसको किसी कीमत पर रोका नहीं जा सकता था, इस खर्च का करना निहायत जरूरी था।

स्पीकर साहब, अगले साल के लिए जो हमने प्रावधान किया है, उसका देखने से मालूम होगा कि अगले साल का नान प्लान का खर्चा पिछले साल से कम है। बजट पर बहस के दौरान मेरे साथियों ने जो वि. 11 बात कही वह यह कही कि यह बजट इन्फ्ले. 11 को नहीं रोकेगा। स्पीकर साहब, इन्फ्ले. 11 की

इम्पलीके इन को रोकना किसी एक स्टेट की बस की बात नहीं है। यह प्रैब्लम इन्टर स्टेट ही नहीं बल्कि इसके रैप्रक एन्ज इन्टरनेशनल होते हैं। फर्ज करो पेट्रोल के एक बैरल का रेट बढ़ जाए तो घरोंडा के पेट्रोल पम्पर पर भी इस मंहगाई का असर पड़ेगा। अगर आसाम में स्ट्राईक होती है तो उसाक असर हरियाणा स्टेट पर भी पड़ेगा क्योंकि इन्फले इन की स्थिति ही कुछ ऐसी है और इन हालात में एक छोटी सी स्टेट यही कर सकती है कि अपने खर्चों पर पाबन्दी लगाए और आयंदा के लिए खर्च कम करे। अगर इस बजट को इस नजरिए से देखा जाए तो कन्कलूडिंग रिकावर्स यही हैं कि हरियाणा में जितना डैफिसिट बजट है उसमें से 30 करोड़ के लगभग सिर्फ इकोनोमी मैयर्ज उठा कर मीट करेंगे, न कि टैक्स लगा कर। जो सिस्टम इस वक्त है इसको रैनेलाईज करेंगे। इसके अलावा अगल बात में यह कहना चाहूंगा कि हमारे पुराने वित्त मंत्री चौधरी सतवीर सिंह जी ने खुद भी इकोनोमिक मैयर्ज उठाने के लिए सुजै इन दी थी। जो कुछ उन्होंने कहा वह चीज पहले ही हमने अपनी बजट स्पीच में इनकारपोरेट कर दी थी। स्पीकर साहब, हमीर स्टेट में जितनी अंडरटेकिंगज हैं, उनकी सहायता के लिए बजट में एक मद रखी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अंडरटेकिंगज अपने मैनेजमेंट को इम्पूव करके कमि यिल लाइन्ज पर चल कर कामयाब होंगी। जब ये कमि यिल लाइन्ज पर चलेंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत हद तक वेस्टफुल एक्पैंडीचर को रोक सकने में कामयाब होंगे। जो सिक यूनिट्स हैं, उनको

प्रौफिफटेबल बनाकर, ऊपर उठाकर चलायेंगे ताकि डैफिसिट गैप को पूरा किया जा सके ।

श्री मूल चन्द जैन: क्या आप बताएंगे कि पिछले डेढ़ वर्ष में आपने क्या किया है ? (व्यवधान)

चौधरी खुरीद अहमद: स्पीकर साहब, जब बाबू जी ने अपना बजट पेश किया था तो उस वक्त बाबू जी का बजट इतना बढ़िया था कि आज तीन साल के बाद चौधरी सन्त कंवर जी की समझ में आया कि वह बजट फाड़ने के काबिल नहीं था, पढ़ने के काबिल था। (व्यवधान) बड़ी देर के बाद उनको यह बात सूझी कि उस बजट में बड़ी काम की बातें थीं। 1978-79 में चौधरी सतवीर सिंह मलिक ने बजट पेश किया था, उसमें 210 करोड़ रुपये की प्लानिंग रखी थी और अचीवमेंट 193 करोड़ की थी। 17 करोड़ रुपये का भार्टफाल देकर डैफिसिट गैप को पूरा कर गये थे। (हंसी) बड़ी अच्छी काउंटिंग है इनकी। अब आप इसके आगे सुनिए। उसके बाद बाबू जी के हाथ में बागडौर आई। इन्होंने 1979-80 के बजट में 219 करोड़ रुपये की प्लानिंग पेश की और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में भी बड़ी दयादिली दिखाई।

श्री मूल चन्द जैन: मैं तो तीन महीने ही फाईनैस मिनिस्टर रहा। बजट बनने के बाद अगर कोई भार्टफाल आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है।

चौधरी खुर गीद अहमद: जनाब, मैं एक बात कहूंगा कि हर ईमारत की एक बेसिक फाउंडेशन होती है। बाबू जी ने जो बुनियाद रखी वह इतनी मजबूत थी कि वे अपनी उस प्लान के पैसे को पूरा नहीं रख सके, वह इतनी मजबूत थी कि जितने टैक्स मैयर्ज उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, वे मेरे भाई संत कंवर और सतबीर सिंह मलिक ने यही फाउंडेशन दिए। इनकी जो बजट स्पीच थी, उसको यही फाउंडेशन दिया गया। फिर इन्होंने कुछ टैक्स लगाए। (विधन) बाबू जी, जब भी टैक्स लगाते हैं तो फार्म सैक्टर की तरफ इनके कदम तेज बढ़ते हैं। नतीजा यह हुआ कि उन सारे टैक्स को इनको विदरू करना पड़ा। मारा इन्होंने किन-किन को था ? पहले तो हलवाइयों को इन्होंने लिया। हलवाई बेचारे कितना टैक्स दे सकते थे ? उनको इनसे मुक्त कराया। फिर रोड टैक्स इन्होंने लगाया, इम्पोर्ट पर लगा दिया और परचेज पर लगा दिया। (विधन)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, जो टैक्स मैंने लगाया था उसको इस गवर्नमेंट ने पहले तो गलती से वापिस कर लिया था लेकिन अब उसे फिर कंसाइनमेंट टैक्स के रूप में लगा रहे हैं और फिर भी मेरी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। (विधन)

चौधरी खुर गीद अहमद: स्पीकर साहब, इनके समय में तो यदि कोई आदमी मवे गी मेले में गाय लेने चला जाता था या बैल का सौदा करलेता था तो उसे भी टैक्स देना पड़ता था। (विधन)

श्री मूल चन्द जैन: मियां जी आप तो एक महीने से फाईनैस मिनिस्टर बने हैं। आप को पता ही क्या है कि फाईनैस क्या होता है ?

चौधरी खुर गिद अहमद: स्पीकर साहब, मैं बाबू जी से पूरी हमदर्दी रखता हूँ। मुझे तो एक दो महीने से चांस मिला है लेकिन बाबू जी को दो दो बार चांस मिल लिया है लेकिन फाईनैस इतना कम्पलिकेटिड सबजैक्ट है कि इसे ये अब तक समझ नहीं पाएं। (विघ्न) वैसे ये बुजुर्ग हैं, जंजाब में अपने समय में फर्स्ट भी आए थे लेकिन अब करें क्या, उमर का तकाजा है। साथ ही साथ स्पीकर साहब, अगर ना उम्मेदी ज्यसादा बढ़ जाए तो इन्सान में फसट्रे इन भी आ जाती है। स्पीकर साहब बजट पर बोलते बोलते एक मौका ऐसा आया कि बाबू जी बहुत जजबाती हो गए। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं ? मुझे तो ऐसा लगा कि ये किसी का सिर फोड़ेंगे। (विघ्न) इन्होंने यह भी कहा कि भाख हड़ताल पर बैठ कर मैं जान दे दूंगा। बाबू जी हम आपकी इज्जत करते हैं। (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: ला एण्ड आर्डर की सिचुए इन के लिए तो कुछ करो। (विघ्न) हिसार में जो कुछ हो रहा है, जहां से चीफ मिनिस्टर स्वयं ताल्लुक रखते हैं, उसके लिए कुछ करो। मेरी हंसी उड़ाने की बजाए ला एंड आर्डर की सिचुए इन के बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। (विघ्न)

चौधरी खुर गीद अहमद: स्पीकर साहब, ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान पर बोलते बोलते बाबू जी इतने जजबाती हो गए कि बजाए कोई हल बताने के ये खुद खुदकु ि कर लें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी मरदानगी है ? इतना ना उम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है।

Mr. Speaker: Let us leave the law and order situation and restirct ourselves to the budget.

चौधरी खुर गीद अहमद: जनाब, सो ाल प्रोग्राम जितना भी लोगों की भलाई के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया हे, वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे साथ राठी साहब ने, जिनके पास भी कुछ दिन इस महकमे का चार्ज रहा है, कहा कि हरिजनों के लिए क्या किया गया है ? सर, हरिजनों के बारे में, बैकवर्ड क्लासिज के बारे में, पिछडे हुए लोगों के बारे मे हमने जो कुछ यिका है उसके बारे में हाउस के सामने बहुत सी बाते आ चुकी हैं लेकिन मैं भी उन सारी स्कीमों का जिक्र यहां करना चाहूंगा, जो गरीब लोगों के लिए हमने तैयार की हैं। सबसे पहले हरिजन कल्याण निगम के तहत हमने यह किया है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी कम से कम दस हजार फैमिलीज को एक साल के अन्दर हम कर्जे देंगे। वह कर्जा क्या होगा ? वह टोटल कर्जा नहीं होगा जैसा कि हमारे साथियों ने समझा है। जो हम देंगे, वह सबसिडी होगी। उसके हिसाब से बैंकों और दूसरे लोगों से कर्जे दिलाएंगे। बाबू जी ने हिसाब

लगाया कि इन लोगों की बाआदी 32 लाख है और लगभग 3 लाख 21 हजार फैमिलीज है। इनके हिसाब से इनको कवर करने में लगभग 32 साल लगेंगे। लेकिन यह बात नहीं है। हम करीब 50 हजार फैमिलीज को हर साल कवर करेंगे और सात साल में तमाम फैमिलीज को कवर करके गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाएंगे। (विधन) हरिजन कल्याण निगम की तरफ से 10 हजार और ऐडिशनल फैमिलीज को हम कर्जा देंगे। वह कर्जा इसके अलावा होगा। स्पीकर साहब, बैंकवर्ड क्लासिज निगम को एक करोड़ रूपया हमने दिया है। (विधन एवं भाोर)

स्पीकर साहब, 1981-82 की हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान्स हैं उनके तहत 35 करोड़ 57 लाख रूपया एक साल के अन्दर हमने हरिजनों के उत्थान के लिए लगाना है। इतनी बड़ी रकम इस क्लास की बहबूदी के लिए पहली बार खर्च की जा रही है। (सत्ताधारी पक्ष से प्रतिक्रिया) स्पीकर साहब, पुरानी स्कीमें भी चल रही हैं जैसे 1980-81 में हमने गरीब हरिजन लड़कियों को दस रूपये फी लड़की के हिसाब से वजीफा दिया है। (विधन) इस तरह से अध्यक्ष महोदय, हमने हरिजनों के लिए बहुत काम किया है। आज से पहले कभी भी एक साल के अन्दर हरिजनों के लिए इतना काम नहीं हुआ था। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों को करने के बाद सात साल के अन्दर इन लोगों को हम गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे।

जनाव स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर के बारे में मेरे आनरेबल साथ चौधरी सतबीर सिंह मलिक ने, जो स्वयं भी फाईनैस मिनिस्टर रह चुके हैं, जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्राप इं योरैंस स्कीम बनाई थी। सारे कागजात मैंने मंगवाए और देखे लेकिन उनमें क्या निकला ? इन्होंने कहा था कि एक रूपया फी एकड़ लेकर हम क्राप इं योरैंस करा देंगे। (विधन) एक कोई कमेटी बनी थी, उसके ये भी मैम्बर थे। जनरल इं योरैन्स कार्पोरे इन के सामने इन्होंने तजवीज पे 1 की कि एक रूपया फी एकड़ हम देंगे और आप सिर्फ ऑलो के अगेन्सट जमींदार को फसलों का बीमा कर दीजिए। लेकिन जी.आई.सी. ने उस स्कीम को मंजूर नहीं किया। इस तरह से वह स्कीम इनके वक्त में ही समाप्त हो गई। आज हमारी बातचीत जी.आई.सी. के साथ चल रही है। आज हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक कैलेमिटी के अगेन्सट इं योरैन्स हो। जो गरीब किसान अपनी मेहनत और पसीने से खेत में फसल बोते हैं लेकिन वे उसकी पूरी प्रोडक्ट इन नहीं ले पाते हैं उसके लिए हमने यह किया है कि जमींदारों को कम्पनसै इन दिया जाये। जी.आई.सी. से हमारी बातचीत चल रही है। कल तक की जो हमारी स्टेज थी, उसकी पोजी इन यह है कि वे कुछ कम्पैक्ट एरिया को लेना चाहिते हैं यानि कुछ तहसीलों को ले लेंगे। वे कहते हैं कि जिस तरह से दूसरे सूबों में किया, उसी तरह से यहां भी करेंगे। दी स्टेट्स हैं जहां पर जी.आई.सी. के माध्यम से क्राप्स की इन् योरैन्स हुई है। हम पहले पैडी और बाजरे की क्राप्स को इस स्कीम के तहत लेना चाहते हैं। हमारी

स्कीम है कि चाहे किसी तरह से भी फसल का नुकसान हो जाये उसका मुआवजा इन् योरेन्स कम्पनी और सरकार मिल कर किसान को दें यानि किसान के नुकसान को पूरा किया जाये। किसी प्रकार की भी कलैमेट्री हो जाये उसके लिए पूरा पैसा दिया जाये।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। पैडी और बाजरे की फसल के टाईम पर तो ओले नहीं पड़ते हैं। गेहूं और चने की फसल के टाईम पर ओले पड़ते हैं, इन फसलों का बीमा होना चाहिए। सरसों की फसल का भी इससे नुकसान हो सकता है।

Mr. Speaker: I draw your attention to Sub-rule (6) of Rule 112 which says:-

“(6) A member shall not raise a point of order:-

(a) to ask for information, or

(b) to explain his position.....”

So, this is no point of order.

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह था कि पैडी और बाजरे की फसल के समय तो ओले पड़ते ही नहीं है। (तोर)

श्री अध्यक्ष: वे यह कह रहे हैं कि ओलों से यह किसी भी चीज से किसानों को नुकसान होगा, उसके लिए इन् यारैन्स

की जायेगी। उस नुकसान का सारा पैसा जी.आई.सी. और सरकार देगी।

चौधरी खुर ग़द अहमद: मैं फिर हाउस को बताना चाहता हूँ कि किसान को किसी भी तरह का नुकसान हो, हम क्राप इन् योरैन्स स्कीम के तहत उस नुकसान को देंगे।

स्पीकर साहब, हमारे साथी चौधरी रण सिंह मान ने बहुत अच्छी सुजै ग़ज दी है। उन्हें ज्यादा आपटीमिस्ट नहीं होना चाहिए। हम जो वायदे करते हैं उन्हें प्लान के अन्दर पूरा करने की कोशिश करते हैं यही तो हमारी सरकार का कमाल है। हर डिवैल्पमेंट पसन्द सरकार का यह कार्य है कि जो भी बात कहे, उसे पूरी करे। हमारे से पहले जो सरकार थी, उसके चीफ मिनिस्टर पहले दो घूंट मार कर सो जाया करते थे। (हंसी)

एक सदस्य: घूंट मार कर नहीं, गोली खा कर सो जाया करते थे। (हंसी)

चौधरी खुर ग़द अहमद: चलो गोली खा कर सोया करते होंगे लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे हनीं है। स्पीकर साहब, चौधरी रण सिंह मान ने जो तजवीज हाउस में रखी है कि किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों का कर्जा माफ किया जाना चाहिए, यह बात करागर नहीं हो सकती। कर्जा माफ करना तो किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। कर्जा माफ करने के बारे में तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से भी क्रिटिसिज्म हुआ

है। हां, यह तो हो सकता है कि मुसीबत के टाइम पर उनको रिलीफ दिया जाये। उनके कर्जों को पोस्टपोन कर दिया जाये या इन्ड्रैस्ट माफ कर दिया जाये लेकिन पूरे कर्ज को माफ नहीं किया जा सकता।

उन्होंने एक बात यह भी बतायी कि मैचिंग ग्रान्ट्स के केसिज बहुत ज्यादा पैडिंग हैं। मैं, जो उन्होंने मिसाल दी थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में चिड़िया गांव है। वहां पर लोगों ने कुछ पैसा जमा करके सरकार को दिया था लेकिन उसके बदले में सरकार ने ग्रान्ट नहीं दी। मैं हाउस की तथा श्री रण सिंह जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उनका जो एस्टीमेंट आया था, वह सैंकान हो गया लेकिन उस पैसे से जितनी उनकी रिकवायरमेंट थी, वह पूरी नहीं होती थी। जितना उनका ग्रान्ट का हक बनता था, वह हमने पूरा दे दिया था। हमने उनको दो लाख 56 हजार 416 रूपये दे दिये लेकिन वहां पर जो बिलिंडग बनेगी उससे वह पूरी नहीं होती है। उसका खर्चा फालतू बनता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि बाकी जो कम्पोनेन्ट है अगर उसका एक हिस्सा वे अपने आप दे देंगे तो दो हिस्से मैचिंग के तौर पर हम दे देंगे। हमने पूरी तफती करायी है, उनको मैचिंग ग्रान्ट दे दी है। अगर फालतू एस्टीमेट बनता है तो उसके लिए वे पैस इकट्ठे करें, उनको सरकार की तरफ से जो मैचिंग ग्रान्ट बनेगी, वह दे दी जायेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: क्या बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दें ।

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended by ten minutes.

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी खुर शिद अहमद: स्पीकर साहब, एजुके ान के बारे में भी यहां पर जिक्र आया था कि 95 परसेन्ट घाटे को सरकार पूरा करे । इस बारे में सरकार ने फैसला ले लिया है और बहुत से जो स्कूलों के बारे में दूसरी मांग आयी थी, उसको भी पूरा किया है । एजुके ान के बारे में मैं कह सकता हूं कि एजुके ान हैड पर आज तक किसी भी सरकार ने इतना पैसा खर्च नहीं किया, जितना इस साल इस सरकार ने किया है ।

हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ साथियों ने जिक्र किया कि अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है । खासतौर पर कैप्टन मांगे राम ने जिक्र किया है । उन्होंने झज्जर में 25 बैड्ज की बजाए पचास बैड्ज के हस्पताल की मांग की है । इसके लिए स्कीम चल रही है । इस हस्पताल में छः बैड्ज एड करके 31 बैड्ज का बना दिया है । वहां पर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, पूरा करेंगे ।

मैडिकल कालेज रोहतक के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। यहां पर कहा गया कि मैडिकल कालेज की कंटेन्जैन्सी ग्रांट बढ़ायी जाये। उसके लिए भी प्रावधान किया है, कुछ उसे भी बढ़ायेंगे। उस में बहुत से इक्वीपमेंट की इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत है, उसके लिए हम कोर्सा कर रहे हैं। वहां नीरो सर्जरी के लिए भी वहां प्रबन्ध होना चाहिए लेकिन हमारी मैडिकल साइंस उतनी एडवांस नहीं हुई है।

कैप्टन मांगे राम जी ने मांग की थी कि वहां पर एक मैकेनाइज्ड लाण्डरी की स्थापना की जाये। इनका बड़ा अच्छा सुझाव था। अच्छा सुझाव होने के कारण हमने इस काम के लिए इसी बजट में प्रोवीजन कर दिया है।

स्पीकर साहब, किसी भी स्टेट में तब तक इकोनोमी पिक अप नहीं कर सकती जब तक कि इण्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान न दिया जाये। हमारे हरियाणा की इकोनोमी प्राइमरली तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस करती है लेकिन हमें इसको इन्डस्ट्रिलाइज भी करना पड़ेगा। इससे हमारी दो दिक्कतें दूर होंगी। एक तो स्टेट में जो कन्जूमर गुडज और दूसरी गुडज की प्रोडक्शन बढ़ेगी और दूसरी हमारे लोगों को एम्प्लायमेंट भी ज्यादा से ज्यादा मिल पायेगी। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा से आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। जिस तरह से स्मला स्केल यूनिट्स हैं उनमें वर्ष 1980-81 के अन्दर बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी तकरीबन 4600 यूनिट्स की है जिससे बहुत से लोगों को

एम्पलाएमेंट मिली है और बहुत सारी प्रोडक्शन भी बढ़ी है। इनकी प्रोडक्शन की और बढ़ान के लिए स्टेट की तरफ से उन्हें इन्सैनिटिव भी दिया जायेगा। जब तक उनकी पूरी मदद नहीं की जायेगी उस समय तक ये पूरी तरह से पनप भी नहीं सकेंगे। हमारी यह उम्मीद है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के मामले में हमारी स्टेट अन्य स्टेटों से आगे चली जायेगी। हम उनकी सहायता के लिए 15 प्रति टात कै 1 सबसिडी की एग्जम्पशन दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प ड्यूटी की भी एग्जम्पशन दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम उनको 3 साल से लेकर 7 साल तक इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी में भी एग्जम्पशन दे रहे हैं। औकट्राय ड्यूटी परचेज सेल्ज टैक्स में भी एग्जम्पशन दी गई है। प्राईस प्रैफरेंस में भी उनको 20 प्रति टात की छूट दी गई है और 100 प्रति टात एडीशनल इन्ट्रैस्ट फ्री लोन भी रखा है। सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स में भी उनको छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ मार्किटिंग असिस्टैन्स भी उनको दी गयी है। इस तरह से हम चाहते हैं कि हरियाणा के जो मेहनतकश लोग हैं जो मेहनत का काम कर रहे हैं, उनको अपनी इकोनोमी बढ़ाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। जब इस तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी तो बेरोजगारी भी काफी हद तक दूर हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो बात बाबू मूल चन्द जैन जी ने और दूसरे साथियों ने ला एण्ड आर्डर के बारे में कही थी उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ला एण्ड आर्डर के

बारे में यहां पर हमारे और भी बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ बातें कहीं हैं। मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जो क्रिमिनल केसिज में इस समय वृद्धि हुई है वह केसिज की रिजस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत न आने के कारण हुई है। पहले लोगों को केस दर्ज कराने में काफी दिक्कत होती थी जिसके कारण वे केस रिजस्ट्रेशन नहीं करवाते थे लेकिन अब इस सरकार ने उस दिक्कत को दूर कर दिया है। यही वजह है कि इस साल में यानी 1-1-1980 से लेकर 28 फरवरी 81 तक के आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है। इस दौरान में 38885 केस रिजस्ट्रेशन हुए हैं और पिछले साल इन केसों की संख्या 37646 थी। इस प्राकर से हमारी पुलिस के सामने जैसी स्थिति थी, उसके अनुसार उसने बड़ा अच्छा कार्य किया है और स्थिति पर काबू पाया है। जहां कहीं पर रिकवरी की जरूरत थी, जहां कहीं पर ट्रेस की जरूरत थी, उसके बारे में मैं यह कह सकता हूं हमारी पुलिस ने एक सबूत दिया है और बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। अगर हमारी पुलिस पर कुछ ज्यादा खर्चा हुआ है तो वह पुलिस की बेहतरी के लिए ही हुआ है। हमारी पुलिस ने हर जगह पर ला एण्ड आर्डर पर कंट्रोल किया है।

स्पीकर साहब, हमारे प्रदेश के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति अन्य स्टेटों की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है।

Mr. Speaker: Khurshid Sahib, would you like that time should be extended further.

चौधरी खुर गीद अहमद: स्पीकर साहब, मैं एक मिनट में ही खत्म कर देता हूँ।

हमारे दूसरे महकमों की भी कारगुजारी बहुत अच्छी है और जिन महकमों के जरिये सरकार की आमदनी बढ़ती है, उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। हमारे एक्साइज एण्ड टैक्स इन्डिपार्टमेंट की डिफरेंट पालिसी के तहत टैक्सों की बहुत ज्यादा कुलैव इन हुई है। जनरल सेल्ज टैक्स और सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स में 82 करोड़ 20 लाख से 94 करोड़ 75 लाख रुपये और सारी मदों के तहत पिछले साल के मुकाबिले 157 करोड़ 78 लाख रुपये से बढ़ कर 171 करोड़ 10 लाख रुपये की आमदनी इस साल फरवरी, 1981 तक हुई है। यहां पर बहुत सी ऐसी बातें पर्सनल रूप से भी कही गई हैं, उनकी बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता था लेकिन जब कोई आदमी बहुत नीचे चला जाये और ऐसे आदमियों को हिट करे जो इस हाउस में अपने आपको डिफैन्ड न कर सके तो यह बात ठीक नहीं है। मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ी है कि हमारे एक आनरेबल मैम्बर ने एस.डी.एम., पानीपत के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। इतनी गलत ओर बेबुनियाद बातें, उन लोगों के बारे में कही जाये जिनसे पर्सनल झगड़ा हो जाये, बड़ी गलत बात है। मैं यह बता देता हूँ कि एक मैम्बर साहब का सीमेन्ट की अलाटमेंट के मामले पर एस.डी.एम. से झगड़ा हुआ। जहां उन्होंने मकान बनाया, वह गलत जगह बनाया। कोर्ट ने से आर्डर कर दिया क्योंकि वह

मकान अपनी जायदाद पर नहीं बल्कि म्युनिस्पल कमेटी की जायदाद पर बना रहे थे। (गेम भोम की आवाजें)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बाद में टाईम दूंगा।

चौधरी खुरशीद अहमद: कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन इन स्टेट कर दिया। कंस्ट्रक्शन इन स्टेट होने के बाद भी जो रिपोर्ट मेरे पास फील्ड से आयी है, उसके मुताबिक यह कहा गया है कि 3 फरवरी को आनरेबल मैम्बर ने वहां पर एस.डी.एम. से कहा कि मझे अढ़ाई सौ बोरी सीमेन्ट का कोटा दिया जाये। एस.डी.एम. ने जवाब दिया कि आपके लिये सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट ने 700 बैगज रिकमेंड किये थे जिसमें से 600 बैगज आप ले चुके हो, 100 बैगज आपको दे दिये जायेंगे। इस पर मैम्बर साहब उस अफसर से नाराज हो गये और उसे धमकी दी गयी कि तुम्हारी खाल असैम्बली के अन्दर उधेड़ूंगा। जनाब, मैं आपसे यह कहूंगा कि इस आगस्ट हाउस को, इस फोरम को इस बात के लिए इस्तेमाल करना कि फील्ड स्टाफ को यहां पर अननसैसरली क्रिटीसाईज किया जाये, यह कहां तक मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि फील्ड स्टाफ को धमकी देना कि वह हाउस में उसकी खाल उधेड़गा, यह हाउस की मर्यादा के विरुद्ध है। अगर कोई अफसर गलत बात करें या कहे तो उसके विरुद्ध राइटिंग में आपको दिया जा सकता है या चीफ मिनिस्टर

साहब को दिया जा सकता है लेकिन इस आगस्ट हाउस का, इस फोरम का गलत इस्तेमाल करना कहां तक जायज है, यह आप खुद ही देख लीजिए। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी अफसर से कोई नाराजगी हो जाती है तो यहां पर उस बात को उछाला नहीं जाना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: क्या बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दें।

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended by another 5 minutes.

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी खुर गिद अहमद: मैं यह कहूंगा कि हाउस को इन चीजों के लिए इस्तेमाल न किया जाये। कल चौधरी राम लाल वधवा भी कुछ गलत आंकड़े पढ़ गये। जब वे हरियाणा बजट एट ए ग्लान्स के पेज 22 को रैफर कर रहे थे तो वे बात तो पर—कैपिटल इन्कम के आंकड़ों की कह रहे थे लेकिन वास्तव में स्टेट इन्कम के आंकड़े पढ़ गए। उनकी बातों का मैं क्यसा जवाब

दू ? चौधरी रिजक राम की मैं क्या बताऊं (व्यवधान व भाोर) वह तो हमारे घर की बात है। कामरेड भांकर लाल जी ने बड़ा भारी अध्ययन किया 49 करोड़ का डैफिसिट दिखाकर। जो 37 करोड़ रुपया पिछले साल का कैरी ओवर होना था, उसको भी उसमें भाामिल कर लिया। इतना घाटा उन्हाँने बढ़ा कर दिखा दिया। मैं यह कहूंगा कि उनकी इस गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है लेकिन खुदा के लिए हजूर (श्रीमति सुशमा स्वराज की तरफ इ तारा करते हुए) वे पढ़ कर तो आ जाया करें, सही तो पढ़ा करें ताकि किसी को उन्हें पढ़ाने की जरूरत ही न पड़े। (हंसीं)

Smt. Sushma Swaraj: On a point of order, Sir. This remark of the Finance Minister is a reflection on the Hon. Member. It should be expunged (Interruptions) It is an aspersion on the Member कि मैं उनको पढ़ाकर लाती हूँ। (व्यवधान व भाोर) जैसे वे खुद कुछ जानते ही नहीं हैं।

Mr. Speaker: I will study. If there is something objectionable, I will expunge it.

चौधरी खुर ग़द अहमद: स्पीकर साहब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: मेरा उर्दू का नौलेज इतना ज्यादा नहीं है। मुझे जरा यह तो बता दीजिए कि हजूर का क्या मतलब होता है ?

Ch. Khurshid Ahmed: The most respected, Sir.

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह हजूर कौन है ? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी खुर गद अहमद: जिनकी मैं इज्जत करता हूँ जिनका मैं। आदर करता हूँ, उनके लिए मैं यह भाब्द इस्तेमाल करता हूँ। स्पीकर सहब, मेरा किसी भी मैम्बर पर आक्षेप करने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब तो यह था कि इनको सही फ़ैक्टस कहने चाहिए थे। जो हमारे कामरेड साहब ने 49 करोड़ का डैफिसिट बताया है, इसमें इन्होंने पिछले डैफिसिट को भी भामिल कर लिया है।

कामरेड भांकर लाल: मैंने कहा था कि सम्पति का ब्यौरा दो। यह जो कारों का और टी.ए. डी.ए. वगैरह का खर्चा है, इसको कम करो।

चौधरी खुर गद अहमद: हमने अपने बजट में फिजूलखर्ची को कम करने के लिए पिछले पैरा में कहा है कि सेविंग करेंगे। हम 12 करोड़ रूपये की सेविंग करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी स्कीमें हैं, उन तमाम स्कीमों के तहत सेविंग करके हमें आता है कि इस 49 करोड़ रूपये के डैफिसिट को हम 30 करोड़ तक ले आयेंगे। इकौनोमी मैयर्ज का एडाप्ट करके और वैस्टफुल एक्सपैन्डिचर को खत्म करके हम इस घाटे का कम करेंगे। बाकी के लिए हम कोशिश करेंगे कि वह भी इसी तरह से पूरा हो जाये ताकि हम हरियाणा का निर्माण कर सकें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

चौधरी सतवीर सिंह मलिक द्वारा

Ch. Satvir Singh Malik: Sir, you had assured me to give some time for personal explanation. Kindly permit me now.

Mr. Speaker: You can give personal explanation for one minute.

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि एस.डी.एम. से मुझे कोई गिला िकवा नहीं है, कोई मेरी उससे जाति दु मनी नहीं है। मैंने जो बात हाउस के अन्दर बतायी थी, वह वही बात बताई थी जो उन्होंने मुझे कही थी। उसके बाद इन्होंने यह कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर मकान बनाया

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): मैंने यह कहा था कि कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, आपको पता है कि एम.एल.एज. को 60 हजार रूपया गवर्नमेंट की तरफ से मकान बनाने के लिए कर्जा मिल जाता है। वहां से मैंने सर्टीफिकेट लिया है। मौके पर इंजीनियर म्यूनिसिपल कमेटी ने जाकर देखा है। यह गलत जगह है या ठीक जगह है, यह तो उसने देखना था। नक ा उन्होंने पास किया। पहले पलिनथ लैवल तक आय गया और फिर रूफ लैवल तक आ गया और इस समय मेरा मकान

कम्पलीट है। यह राजनैतिक विरोध के कारण यहां पर गलत ब्यानी कर रहे हैं। इनको इस किस्म के एलोगे उन नहीं लगाने चाहिए।

Mr. Speaker: The House is adjourned till 2.30 p.m.

आवाजें: नहीं जी, 3.00 बजे ठीक रहेगा।

Mr. Speaker: All right, the House stands adjourned till 3.00 p.m. today.

13.45 बजे

(The Sabha then adjourned till 3.00 p.m. today i.e. the 24th March, 1981)